

GUPTA

CLASSES

CURRENT AFFAIRS

JULY 2023

Hindi

Part-1



GUPTA

CLASSES

Current Affairs Q&A PDF – July 2023

Table of Contents

NATIONAL AFFAIRS	6
INTERNATIONAL AFFAIRS	52
GOVT SCHEMES	62
VISITS	64
BANKING AND FINANCE	68
ECONOMY AND BUSINESS	94
MoU's AND AGREEMENTS	101
APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS	111
AWARDS AND RECOGNITIONS	123
SUMMITS AND CONFERENCES	134
COMMITTEE AND MEETING	136
INDEX	137
ACQUISITION AND MERGERS	140
DEFENCE	142
SCIENCE AND TECHNOLOGY	145
SPORTS	158
BOOKS AND AUTHORS	170
OBITUARY	171
IMPORTANT DAYS	174
APP and WEB PORTAL	187
CURRENT STATIC BANKING	189
CA STATIC GK	191

NATIONAL AFFAIRS

1. नई दिल्ली, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान जारी पंचायत विकास सूचकांक (PDI) पर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के राज्य मंत्री (MoS) कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंचायत विकास सूचकांक (PDI) पर रिपोर्ट जारी की।

B) PDI रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के 9 विषयों पर 144 स्थानीय लक्ष्यों, 577 स्थानीय संकेतकों और 688 डेटा बिंदुओं के साथ आती है।

C) पायलट आधार पर, महाराष्ट्र के 4 जिलों (पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर) से डेटा संकलित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के 4 जिलों में 70% पंचायतें श्रेणी C में हैं, जबकि 27% B में हैं।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

28 जून 2023 को, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के राज्य मंत्री (MoS) कपिल मोरेश्वर पाटिल ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित PDI पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान पंचायत विकास सूचकांक (PDI) पर रिपोर्ट जारी की।

i. PDI को गांवों में लक्षित विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया था।

ii. PDI रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के 9 विषयों पर 144 स्थानीय लक्ष्यों, 577 स्थानीय संकेतकों और 688 डेटा बिंदुओं के साथ आती है, जो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को एकत्रित करती है।

iii. पायलट आधार पर, महाराष्ट्र के 4 जिलों (पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर) से डेटा संकलित किया गया था।

- पायलट सूचकांक के आधार पर, महाराष्ट्र के 4 जिलों की 70% पंचायतें श्रेणी C में हैं, जबकि 27% पंचायतें B में हैं।

iv. MoPR ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ 2022-23 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पुनर्जीवित करने की भी मंजूरी दे दी है।

2. जून 2023 तक स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "गलत" है?

A) वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा यात्रा पैकेजों के लिए, भुगतान के तरीके की परवाह किए बिना, प्रति वर्ष व्यक्तिगत 7 लाख रुपये तक की राशि के लिए TCS की दर में कोई बदलाव नहीं होगा।

B) 7 लाख रुपये की सीमा से परे, शिक्षा ऋण द्वारा वित्तपोषित शिक्षा के लिए प्रेषण के लिए TCS 0.5%; शिक्षा या चिकित्सा उपचार के लिए प्रेषण के लिए 5% और अन्य के लिए 20% होगा।

C) TCS दरों में जो बदलाव 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले थे, वे अब उपर्युक्त संशोधनों के साथ 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे।

1) केवल A

2) केवल B

3) केवल C

4) केवल A & B

5) केवल B & C

उत्तर-3)केवल C

स्पष्टीकरण:

28 जून 2023 को, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत सभी उद्देश्यों के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की दर और विदेशी यात्रा पैकेजों के लिए, भुगतान के तरीके की परवाह किए बिना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।

- यह भी घोषणा की गई कि संशोधित TCS दरों के कार्यान्वयन और LRS में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जाएगा।

i.सरकार ने अपनी 16 मई 2023 की ई-गजट अधिसूचना के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है, जिसने क्रेडिट कार्ड खर्चों को LRS के तहत लाया था।

ii.TCS दरों में जो बदलाव 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले थे, वे अब उपर्युक्त संशोधनों के साथ **1 अक्टूबर 2023** से लागू होंगे।

TCS दरों में बदलाव का अवलोकन:

भुगतान की प्रकृति	वित्त अधिनियम 2023 से पहले की दरें	1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी नई दरें
ऋण द्वारा वित्त पोषित शिक्षा के लिए LRS	7 लाख रुपये तक शून्य	7 लाख रुपये तक शून्य
	7 लाख रुपये से ऊपर 0.5%	7 लाख रुपये से ऊपर 0.5%
चिकित्सा उपचार/शिक्षा के लिए LRS (ऋण द्वारा वित्तपोषित के अलावा)	7 लाख रुपये तक शून्य	7 लाख रुपये तक शून्य
	7 लाख रुपये से ऊपर 5%	7 लाख रुपये से ऊपर 5%
अन्य प्रयोजनों के लिए LRS	7 लाख रुपये तक शून्य	7 लाख रुपये तक शून्य
	7 लाख रुपये से ऊपर 5%	7 लाख रुपये से ऊपर 20%
विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद	5% (सीमा के बिना)	7 लाख रुपये तक 5%, उसके बाद 20%

3. जून 2023 में जारी FY23 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात आंकड़ों के अनुसार, कौन सा राज्य USD 5.37 बिलियन के निर्यात के साथ FY23 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान का अग्रणी निर्यातक बन गया है?

- 1)तमिलनाडु
- 2)कर्नाटक
- 3)उत्तर प्रदेश
- 4)महाराष्ट्र
- 5)आंध्र प्रदेश

उत्तर- 1)तमिलनाडु

स्पष्टीकरण:

FY23 (मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात आंकड़ों के अनुसार, **तमिलनाडु (TN) FY23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भारत का प्रमुख निर्यातक** बन गया, जिसमें निर्यात 5.37 बिलियन (bn) अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो FY22 (1.86 bn अमेरिकी डॉलर) के निर्यात से लगभग तीन गुना है।

- 4.90 bn अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश (UP) दूसरे स्थान पर और 4.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है।
- **पहली बार**, TN ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अग्रणी निर्यातक के रूप में UP, कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है।
- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों के उत्पादन ने TN को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में FY22 में चौथे स्थान से शीर्ष स्थान पर चढ़ने में मदद की।

FY22-23 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 23.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, कुल निर्यात में TN की हिस्सेदारी 22.83% है।

4. जून 2023 में घोषित ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है?

A) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने SIGHT कार्यक्रम: घटक I - "इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए

प्रोत्साहन योजना" और घटक II - "हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना" के कार्यान्वयन के लिए व्यापक

दिशानिर्देशों की घोषणा की।

B) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

C) MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को

ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से SIGHT कार्यक्रम को लागू करेगा।

D) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

E) MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को

ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से SIGHT कार्यक्रम को लागू करेगा।

F) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

G) MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को

ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से SIGHT कार्यक्रम को लागू करेगा।

H) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

I) MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को

ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से SIGHT कार्यक्रम को लागू करेगा।

J) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

K) MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को

ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से SIGHT कार्यक्रम को लागू करेगा।

L) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

M) MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) को

ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से SIGHT कार्यक्रम को लागू करेगा।

N) घटक I को FY 26 से FY 30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

30 जून 2023 को, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप

(SIGHT) कार्यक्रम: घटक I - "इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना" और घटक II - "हरित हाइड्रोजन उत्पादन

के लिए प्रोत्साहन योजना" के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की घोषणा की।

- SIGHT कार्यक्रम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 17,490 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक प्रमुख वित्तीय उपाय है।
- SIGHT कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बनाना है।

i. घटक 1 को FY26 से FY30 तक इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 4,440 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है।

ii. दूसरी ओर, घटक 2 को इसी अवधि के दौरान हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13,050 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

iii. MNRE वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 और FY 2029-30 के बीच कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT) कार्यक्रम लागू करेगा।

5. किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में, गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाने के लिए हेमिस गोम्पा (मठ) द्वारा हाल ही में (जून'23 में) दो दिवसीय हेमिस त्सेचू महोत्सव मनाया गया था?

- 1) जम्मू और कश्मीर
- 2) असम
- 3) लद्दाख
- 4) सिक्किम
- 5) अरुणाचल प्रदेश

उत्तर-3) लद्दाख

स्पष्टीकरण:

हेमिस गोम्पा (मठ) द्वारा 28 जून से 29 जून 2023 तक लेह, लद्दाख में गुरु पद्मसंभव की जयंती पर उनके जीवन और कार्यों को मनाने के लिए वार्षिक दो दिवसीय हेमिस त्सेचू महोत्सव मनाया जाता है, जिन्हें गुरु रिंपोछे के रूप में जाना जाता है।

i. हेमिस त्सेचू महोत्सव गुरु पद्मसंभव का जश्न मनाता है, जिसमें भिक्षु मुखौटे पहनते हैं और झांझ और लंबे सींगों की ताल पर नृत्य करते हैं।

ii. यह महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में बंदर वर्ष के अवसर पर गुरु पद्मसंभव के रेशम थांगका (तिब्बती पेंटिंग) के उद्घाटन का भी प्रतीक है, जो हर 12 साल में आता है।

नोट- गुरु पद्मसंभव ने आठवीं सदी के अंत में जीवन व्यतीत किया, हिमालयी साम्राज्य में तांत्रिक बौद्ध धर्म का परिचय देते थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध आठ अवतारों से लोगों को उपदेश दिया।

6. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जून'23 में) वर्सोवा बांद्रा सी लिंक (VBSL) का नाम बदलकर विनायक दामोदर सावरकर सावरकर के नाम पर 'वीर सावरकर सेतु' कर दिया है?

- 1) ओडिशा
- 2) महाराष्ट्र
- 3) केरल
- 4) आंध्र प्रदेश
- 5) पश्चिम बंगाल

उत्तर- 2) महाराष्ट्र

स्पष्टीकरण:

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई में दो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नाम विनायक दामोदर सावरकर और पूर्व प्रधान मंत्री (PM) अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी दी।

i. 17 km वर्सोवा बांद्रा सी लिंक (VBSL) जो अंधेरी को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ता है और तटीय सड़क परियोजना का एक हिस्सा सावरकर के नाम पर 'वीर सावरकर सेतु' नाम दिया जाएगा।

ii. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, दिसंबर 2023 तक पूरा होने पर भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होने की उम्मीद है, इसका नाम बदलकर वाजपेयी के बाद 'अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु' कर दिया जाएगा।

7. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जून'23 में) गुणवत्ता संकल्प लॉन्च करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) और अन्य उद्योग संघों के साथ सहयोग किया है?

- 1) पश्चिम बंगाल
- 2) उत्तर प्रदेश
- 3) ओडिशा

4)मध्य प्रदेश

5)कर्नाटक

उत्तर-3)ओडिशा

स्पष्टीकरण:

26 जून 2023 को, ओडिशा सरकार ने ओडिशा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के उद्देश्य से भुवनेश्वर, ओडिशा में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प (ओडिशा क्वालिटी मिशन) लॉन्च किया।

i. यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) और अन्य उद्योग संघों जैसे एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (EIPC), ओडिशा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (OASME), PHDचैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के सहयोग से भुवनेश्वर, ओडिशा में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प (ओडिशा क्वालिटी मिशन) लॉन्च किया।

8. जून 2023 में, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने FY24 की दूसरी तिमाही (Q2) के लिए चुनिंदा लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दीं।

जून 2023 तक लघु बचत योजनाओं (SSS) और उनकी ब्याज दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 'गलत' है?

1) वित्त मंत्रालय (MoF), DEA ने FY24 की Q2 (यानी 1 जुलाई, 2023-सितंबर 30, 2023) के लिए चयनित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

2) 5-वर्षीय डाकघरों में एक साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 30 आधार अंक (bps) बढ़ाकर 7.2% से 7.5% कर दी गई है।

3) 1 साल की सावधि जमा के लिए ब्याज दर 10 आधार अंक बढ़कर 6.8% से 6.9% और 2 साल की सावधि जमा के लिए 6.9% से 7% हो गई है।

4) सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और बचत जमा के लिए ब्याज दरों को 7.1% और 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है।

5) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 7.7% की ब्याज दर के साथ अपरिवर्तित बनी हुई है।

उत्तर- 2) 5-वर्षीय डाकघरों में एक साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 30 आधार अंक (bps) बढ़ाकर 7.2% से 7.5% कर दी गई है।

स्पष्टीकरण:

वित्त मंत्रालय (MoF) के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (Q2 FY24)(यानी 1 जुलाई, 2023-30 सितंबर, 2023)के लिए चुनिंदा लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.3% तक की वृद्धि की घोषणा की है।

- दरें बैंकिंग प्रणाली में उच्च-ब्याज दरों के अनुरूप हैं।
- पांच-वर्षीय आवर्ती जमा (RD) के लिए ब्याज दर 30 आधार अंक (bps) बढ़ा दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 0.3% की उच्चतम वृद्धि हुई है। पहले यह 6.2% थी, अब 6.5% है।
- डाकघरों में एक साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 10 bps की वृद्धि हुई है, अब 0.1% की दर से 6.9% (पहले 6.8%) और दो साल की अवधि के लिए 7% (पहले 6.9%) हो गई है।
- लोकप्रिय सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और बचत जमा के लिए ब्याज दरें 7.1% और 4% पर रखी गई हैं।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 के लिए 7.7% पर अपरिवर्तित रही।
- मासिक आय योजना के लिए ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और यह निवेशकों को 7.4 प्रतिशत का लाभ देती है।

9. जून 2023 तक "कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023" के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?
A) विद्युत मंत्रालय ने भारत का पहला घरेलू विनियमित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार विकसित करने के लिए "कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023" को अधिसूचित किया।

B) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 में एक राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC), एक तकनीकी समिति, एक मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी और कार्बन बाजार नियामक के रूप में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का गठन शामिल है।

C) 10 सदस्यों वाली राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय की सचिव लीना नंदन करेंगी।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर- 2) केवल A & B

स्पष्टीकरण:

30 जून 2023 को, विद्युत मंत्रालय ने भारत का पहला घरेलू विनियमित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार विकसित करने के लिए "कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023" को अधिसूचित किया।

- इस स्कीम की घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के तहत की गई थी।
- इस स्कीम का मसौदा ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा तैयार किया गया था।

i. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 में एक राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC), एक तकनीकी समिति, एक मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी और कार्बन बाजार नियामक के रूप में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का गठन शामिल है।

ii. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) भारतीय कार्बन बाजार की रजिस्ट्री होगी।

iii. 20-22 सदस्यों वाली राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव पदेन अध्यक्ष के रूप में करेंगे, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के सचिव सह-अध्यक्ष होंगे।

नोट- ऊर्जा के वर्तमान सचिव श्री पंकज अग्रवाल हैं और MoEF&CC की सचिव सुश्री लीना नंदन हैं।

10. जून 2023 में, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP-3) की तीसरी यूनिट, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 700 MWe दाबित भारी पानी रिएक्टर (PHWR) (परमाणु ऊर्जा रिएक्टर) ने _____ (राज्य) में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया।

1) आंध्र प्रदेश

2) झारखण्ड

3) महाराष्ट्र

4) गुजरात

5) कर्नाटक

उत्तर- 4) गुजरात

स्पष्टीकरण:

30 जून 2023 को, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP) (KAPP -3) की तीसरी यूनिट, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 700 MWe (मेगावाट इलेक्ट्रिक) दाबित भारी पानी रिएक्टर (PHWR) (परमाणु ऊर्जा रिएक्टर) ने गुजरात के काकरापार साइट पर अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।

i. काकरापार परियोजना में दो 700 MW PHWR: KAPP-3 और KAPP-4 का निर्माण शामिल है।

ii. काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP) साइट पर दो 220 मेगावाट PHWR (काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS)-1 और KAPS-2) भी हैं।

iii. रिएक्टर का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग (DEA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) द्वारा किया गया था।

11. जुलाई 2023 में, प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCEM) शुरू किया और _____ (राज्य) में एनीमिया को खत्म करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

- 1) मध्य प्रदेश; 2037
- 2) उत्तर प्रदेश; 2040
- 3) मध्य प्रदेश; 2047
- 4) उत्तर प्रदेश; 2030
- 5) गुजरात; 2027

उत्तर-3) मध्य प्रदेश; 2047

स्पष्टीकरण:

1 जुलाई 2023 को, भारत के प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCEM) शुरू किया और 2047 तक एनीमिया को खत्म करने के लिए शहडोल, मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। NSCEM की पहल के साथ-साथ PM ने लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित किए।

i. PM ने लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्ड के वितरण की भी शुरुआत की, जिसमें मध्य प्रदेश में लाभार्थियों को 1 करोड़ कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

ii. AB-PMJAY कार्ड के वितरण का समारोह पूरे मध्य प्रदेश में शहरी निकायों, ग्राम पंचायतों और विकास खंडों में आयोजित किया जा रहा था।

12. जून 2023 में, केंद्रीय पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने _____ राज्य और पिक्चर पोस्ट कार्ड के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया।

- 1) झारखंड
- 2) आंध्र प्रदेश
- 3) तेलंगाना
- 4) छत्तीसगढ़
- 5) सिक्किम

उत्तर-3) तेलंगाना

स्पष्टीकरण:

30 जून 2023 को, केंद्रीय पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने डाक सदन, हैदराबाद, तेलंगाना में एक कार्यक्रम में "तेलंगाना राज्य के 9 साल" और पिक्चर पोस्ट कार्ड (5 कार्ड का एक सेट) "तेलंगाना में बौद्ध विरासत - बावापुर कुरु" के उपलक्ष्य में एक स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया।

i. धूलिकट्टा बौद्ध स्तूप वाले स्पेशल पोस्टल कवर की कीमत 50 रुपये है और बावपुर कुरु पोस्ट कार्ड के सेट की कीमत 200 रुपये है। ये सभी प्रधान पोस्ट ऑफिस से में उपलब्ध होंगे।

ii. 5 कार्डों का सेट बावरी की घटनाओं, सुट्टानिपाटा के परायणवग्गा से एक ब्राह्मण ऋषि की यात्रा और बुद्ध धम्म की शुरुआत का पता लगाता है।

- तेलंगाना का गठन 2 जुलाई 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में हुआ था।
- 2 जुलाई 2023 को तेलंगाना का 9वां राज्य दिवस है।

13. जुलाई 2023 में संचार मंत्रालय (MoC) द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) टेलिकॉम्युनिकेशन विभाग (DoT), संचार मंत्रालय (MoC) ने टेलिकॉम क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भारत 6G एलायंस (B6GA) लॉन्च किया।

B) 6G प्रौद्योगिकी की प्रगति का समर्थन करने के लिए टेलिकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के माध्यम से 240.51 करोड़ रुपये का अनुदान 6G THz ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम (OAM) के साथ परीक्षण मंच & मल्टीप्लेक्सिंग और उन्नत ऑप्टिकल संचार परीक्षण मंच परियोजना के लिए आवंटित किया गया है।

C) डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्कायर (DCIS) पहल के तहत 66 स्टार्टअप और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को कुल 48 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

3 जुलाई, 2023 को टेलिकॉम्युनिकेशन विभाग (DoT), संचार मंत्रालय (MoC) ने टेलिकॉम क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भारत 6G एलायंस (B6GA) लॉन्च किया। इस संबंध में B6GA वेबसाइट (<https://bhart6galliance.com>) भी लॉन्च की गई।

- B6GA के गठन की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, MoC, देवुसिंह चौहान, संचार राज्य मंत्री (MOS) की उपस्थिति में की गई।

i. B6GA भारत में एक सहयोगी मंच है, जो स्टार्टअप्स, कंपनियों (सार्वजनिक और निजी दोनों), शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, वैश्विक प्रौद्योगिकी गठबंधनों, संघों और मानक विकास संगठनों को एक साथ लाता है।

- B6GA 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुणक के रूप में कार्य करने के लिए 6G प्रौद्योगिकियों को तैनात करेगा।

ii. 6G प्रौद्योगिकी की प्रगति का समर्थन करने के लिए टेलिकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के माध्यम से 240.51 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है।

iii. इस फंड का उपयोग 2 परियोजनाओं: 6G THz ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम (OAM) के साथ परीक्षण मंच & मल्टीप्लेक्सिंग और उन्नत ऑप्टिकल संचार परीक्षण मंच परियोजना के लिए किया जाएगा।

iv. कार्यक्रम के दौरान, डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्कायर (DCIS) पहल के तहत 66 स्टार्टअप और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को कुल 48 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

14. जुलाई 2023 में, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) भारत ने खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए।

निम्नलिखित में से कौन सा देश SARADO का सदस्य 'नहीं' है?

1) श्रीलंका

2) पाकिस्तान

3) भूटान

4) बांग्लादेश

5) नेपाल

उत्तर - 2) पाकिस्तान

स्पष्टीकरण:

3 जुलाई 2023 को, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के डोपिंग रोधी संगठन शामिल हैं, ताकि NADA भारत – SARADO सहयोग बैठक में खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जा सके।

i. यह सहयोग खेलों में डोपिंग प्रथाओं से उत्पन्न चुनौतियों को सामूहिक रूप से संबोधित करने में मदद करता है।

ii. यह समझौता डोपिंग रोधी क्षेत्र में भारत के लिए अपनी तरह के पहले समझौते के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

15. जुलाई 2023 में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए ढांचागत और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए _____ (योजना/फंड) के तत्वावधान में एक विशेष योजना शुरू की।

1) निर्भया फंड

2) संबल योजना

3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

4) बाल संरक्षण योजना

5) वात्सल्य फंड

उत्तर- 1) निर्भया फंड

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्भया फंड के तत्वावधान में एक विशेष योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य उन गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए ढांचागत और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है, जिनके पास अपनी देखभाल करने का कोई साधन नहीं है।

- "बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं या गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय तक पहुंचने के लिए गंभीर देखभाल और सहायता योजना" का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के तहत इन कमजोर व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

i. प्रस्ताव का बजट 74.10 करोड़ रुपये है। आवंटित धनराशि का उपयोग इन पीड़ितों के लिए समर्पित आश्रय स्थापित करने के लिए भी किया जाएगा।

ii. इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों और बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के सहयोग से मिशन वात्सल्य की प्रशासनिक संरचना का लाभ उठाते हुए एक छत के नीचे एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करना है।

16. जुलाई 2023 में, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने _____ (शहर) से भारत भर में 75 ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया।

1) मुंबई, महाराष्ट्र

2) द्वारका, गुजरात

3) पणजी, गोवा

4) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

5) पुरी, ओडिशा

उत्तर-2) द्वारका, गुजरात

स्पष्टीकरण:

1 जुलाई 2023 को, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द्वारका, गुजरात से भारत भर में 75 ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया।

- उन्होंने गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में पहले तीन पुनर्निर्मित प्रकाशस्तंभों का उद्घाटन किया।
- यह उद्घाटन अभियान की शुरुआत का प्रतीक है।

17. भारत सरकार के उस संगठन/शीर्ष निकाय का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और भारत के फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन(RAKEZ) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 1)फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- 2)इंडियन कॉउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
- 3)एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी
- 4)इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर
- 5)इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट

उत्तर-4)इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर

स्पष्टीकरण:

रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन (RAKEZ) और इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (ICFA) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और भारत के फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- i.MoU का उद्देश्य ज्ञान के आदान-प्रदान, व्यापार संवर्धन, निवेश और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के अवसर पैदा करना है।
- ii.यह ICFA जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को मजबूत करने और UAE के लिए रणनीतिक व्यापार और निवेश भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को पहचानने की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

18. किस देश के बंदरगाह विभाग ने हाल ही में (जून'23 में) इंटरनेशनल ट्रेकड पैकेट सर्विस (ITPS) शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ बाइलेटरल ट्रेकड पैकेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं?

- 1)ब्राज़ील
- 2)ऑस्ट्रेलिया
- 3)कनाडा
- 4)मेक्सिको
- 5)जर्मनी

उत्तर-3)कनाडा

स्पष्टीकरण:

संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा 28 जून, 2023 को अधिसूचित भारत के राजपत्र के अनुसार, इंडिया पोस्ट & कनाडा पोस्ट ने ई-कॉमर्स निर्यात की सुविधा के लिए दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेकड पैकेट सर्विस (ITPS) शुरू करने के लिए एक बाइलेटरल ट्रेकड पैकेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

i.यह सेवा 01 जुलाई, 2023 से शुरू हुई।

ii.इंडिया पोस्ट पहले से ही 38 भागीदार देशों के साथ ITPS सेवा प्रदान करता है और कनाडा 39वें स्थान पर होगा।

19. उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में (जून'23 में) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), नई दिल्ली, दिल्ली की दर्शनम गैलरी में दुनिया में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी 'विश्व विरासत पर बैंकिंग' का उद्घाटन किया है। .

- 1)मीनाकाशी लेखी (संस्कृति राज्य मंत्री)
- 2)अमित शाह (केंद्रीय गृह मंत्री)
- 3)G किशन रेड्डी (केंद्रीय संस्कृति मंत्री)
- 4)सुब्रह्मण्यम जयशंकर (केंद्रीय विदेश मंत्री)
- 5)अर्जुन राम मेघवाल (संस्कृति राज्य मंत्री)

उत्तर-1)मीनाकाशी लेखी (संस्कृति राज्य मंत्री)

स्पर्धीकरण:

30 जून 2023 को, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री **मीनाकाशी लेखी** ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), नई दिल्ली, दिल्ली की दर्शनम गैलरी में दुनिया में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी '**विश्व विरासत पर बैंकिंग**' का उद्घाटन किया।

- यह प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा सूचीबद्ध विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थलों को दर्शाने वाले G-20 सदस्य देशों के बैंकनोट प्रदर्शित करती है।

i. यह प्रदर्शनी चल रहे G-20 शिखर सम्मेलन समारोह के हिस्से के रूप में भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और 9 जुलाई 2023 तक चलेगी और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आयोजित की गई है।

ii. प्रदर्शनी का संचालन एक स्वतंत्र विद्वान और 'मनी टॉक्स' की संस्थापक सुश्री रुक्मिणी दहानुकर द्वारा किया गया है।

20. उस हैकथॉन का नाम बताइए जिसे हाल ही में (जून'23 में) संचार मंत्रालय द्वारा 5G उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है।

- 1) 5G & बियॉन्ड हैकथॉन 2023
- 2) स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023
- 3) द ग्रैंड हैकथॉन 2023
- 4) मंथन हैकथॉन 2023
- 5) 5G & ट्रांसफॉर्मेशन & इंडस्ट्री हैकथॉन 2023

उत्तर- **1) 5G & बियॉन्ड हैकथॉन 2023**

स्पर्धीकरण:

संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) '**5G & बियॉन्ड हैकथॉन 2023**' आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य भारत-केंद्रित अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करना है, जिन्हें व्यावहारिक 5G और उससे आगे के उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रतिभागियों में व्यक्ति, छात्र, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, जो 28 जून, 2023 से अपने प्रस्ताव भेजेंगे।

i. अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित आगामी **इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2023** के दौरान 5G उत्पादों और समाधानों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शीर्ष 100 स्टार्टअप को 100 लाख (एक करोड़) के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

21. केंद्रीय बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में (जुलाई'23 में) किस राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) टर्मिनल की आधारशिला रखी है?

- 1) ओडिशा
- 2) आंध्र प्रदेश
- 3) महाराष्ट्र
- 4) गुजरात
- 5) असम

उत्तर- **5) असम**

स्पर्धीकरण:

4 जुलाई 2023 को केंद्रीय बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग (MoPSW) और आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 2) के किनारे डिब्रूगढ़ **असम** के बोगीबेल में विकसित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) टर्मिनल की आधारशिला रखी।

i. पर्यटक-सह-कार्गो IWT टर्मिनल को 46.60 करोड़ रुपये में विकसित किया जाएगा और फरवरी 2024 तक पूरा होने वाला है।

नोट: IWT टर्मिनल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के तत्वावधान में बनाया गया है - MoPSW की अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नोडल एजेंसी, और इसमें कई आधुनिक विशेषताएं होंगी।

22. जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक, 2022 के ड्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "गलत" है?

A) विधेयक में डेटा फिडबैक शिफ्ट को डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने की आवश्यकता है।

B) यह विधेयक डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए 450 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

C) व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड और प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों को सूचित करने में विफलता पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

1)केवल A

2)केवल B

3)केवल C

4)केवल A & B

5)केवल B & C

उत्तर- 2)केवल B

स्पष्टीकरण:

5 जुलाई, 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक, 2022 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे 20 जुलाई से 11 अगस्त, 2023 तक शुरू होने वाले आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।

- विधेयक का उद्देश्य सहमति-आधारित डेटा संग्रह तकनीक प्रदान करना है।
- विधेयक में डेटा फिडबैक शिफ्ट से डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने की आवश्यकता है।
- यह विधेयक डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
- यह आवश्यक मंत्रिमंडल मंजूरी के साथ इस तरह के जुर्माने को अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता है। इस तरह की बढ़ोतरी के लिए कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।
- उद्योग विशेषज्ञों के निरंतर विरोध के बीच बच्चों की परिभाषा को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में बरकरार रखा जाएगा।
- व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड और प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों को सूचित करने में विफलता पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

23. जुलाई 2023 में, गृह मंत्रालय ने _____ रुपये (राशि) के परिव्यय के साथ "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की।

1)6000 करोड़

2)2000 करोड़

3)1000 करोड़

4)5000 करोड़

5)4000 करोड़

उत्तर- 4)5000 करोड़

स्पष्टीकरण:

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत के राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (NDRF) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो के आवंटन के एक भाग के रूप में "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की।

- योजना का कुल परिव्यय **5000 करोड़** रुपये है और इसमें से 500 करोड़ रुपये राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखे गए हैं।

i. उद्देश्य: राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना इस दृष्टि से कि NDRF की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटकों के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की गतिविधियाँ सुनिश्चित की जाएंगी।

ii. फंडिंग: योजना के तहत परियोजनाओं और प्रस्तावों के लिए, राज्य सरकार अपने बजटीय संसाधनों से कुल लागत का 25% योगदान देगी।

- उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (NEH) राज्य ऐसी परियोजनाओं की कुल लागत का केवल 10% योगदान देंगे।

24. उस राज्य/UT का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) जरूरतमंद लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता बढ़ाने के लिए भारत का पहला टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (MANAS) चैटबॉट लॉन्च किया।

1) दिल्ली

2) जम्मू और कश्मीर

3) तेलंगाना

4) महाराष्ट्र

5) पश्चिम बंगाल

उत्तर- 2) जम्मू और कश्मीर

स्पष्टीकरण:

5 जुलाई 2023 को, जम्मू और कश्मीर (J&K) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश (UT) में **भारत का पहला टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (MANAS) चैटबॉट** लॉन्च किया, ताकि जरूरतमंद लोगों के साथ तत्काल बातचीत शुरू करके व्यथित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बढ़ाया जा सके।

i. 2-टियर प्रणाली में राज्य टेली-MANAS सेल शामिल हैं, जिसमें टियर 1 में प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञ और/या टियर 2 में ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए eSanjeevani शामिल हैं।

25. उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) 2,000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए 'अमा पोखरी' योजना शुरू की है।

1) आंध्र प्रदेश

2) महाराष्ट्र

3) पश्चिम बंगाल

4) मध्य प्रदेश

5) ओडिशा

उत्तर- 5) ओडिशा

स्पष्टीकरण:

6 जुलाई 2023 को, ओडिशा के मुख्यमंत्री (CM) नवीन पटनायक ने 'अमा पोखरी' योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ओडिशा के भुवनेश्वर में लोकसेवा भवन में 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2,000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प करना है।

i. 'अमा पोखरी' योजना 120 करोड़ रुपये की लागत से लागू की गई है।

ii. जल निकायों का नवीनीकरण और रखरखाव मिशन शक्ति महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHG) के सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा।

26. जुलाई 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम का उपयोग करके भेजे गए अनुचित और अवैध चिकित्सा उत्पादों की पहचान करने के लिए ऑपरेशन _____ चलाया।

- 1) ब्रॉडर स्वॉर्ड
- 2) ब्लूबर्ड
- 3) लायनफ़िश
- 4) ब्लू लोटस
- 5) गरुड़

उत्तर- 1) ब्रॉडर स्वॉर्ड

स्पष्टीकरण:

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम का उपयोग करके भेजे गए अनुचित और अवैध चिकित्सा उत्पादों की पहचान करने के लिए एक द्विपक्षीय बहु-एजेंसी प्रवर्तन पहल "ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड" का संचालन किया।

i. 12 से 23 जून 2023 तक चलाए गए ऑपरेशन में न्यूयॉर्क, USA के जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और शिकागो, USA के ओ'हारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय मेल सुविधाओं (IMF) के माध्यम से भारत से USA आने वाले शिपमेंट को लक्षित किया गया।

ii. इस युद्ध ऑपरेशन के परिणामस्वरूप गैरकानूनी और संभावित रूप से घातक अस्वीकृत प्रिस्क्रिप्शन दवाओं, संयोजन चिकित्सा उपकरणों और सिंथेटिक दवा अग्रदूतों के 500 से अधिक शिपमेंट को अमेरिकी ग्राहकों तक पहुंचने से रोका गया।

27. जुलाई 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) वित्त मंत्रालय ने गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 को गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल (दूसरा संशोधन) रूल्स, 2023 के साथ संशोधित किया है, जिसके तहत नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRI) को गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में नामांकित होने के योग्य बनाया गया है।

B) इस संशोधन को सब-रूल (8) के बाद रूल 14 में, प्रमुख रूल्स में सब-रूल (9) के रूप में जोड़ा गया है।

C) एक अन्य संशोधन खाताधारक की मृत्यु पर संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।

- 1) केवल A
- 2) केवल A & B
- 3) केवल B & C
- 4) केवल A & C
- 5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

वित्त मंत्रालय ने गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 को गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल (दूसरा संशोधन) रूल्स, 2023 के साथ संशोधित किया है, जिसके तहत नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRI) को गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में नामांकित होने के योग्य बनाया गया है।

• यह इस शर्त पर है कि ऐसे नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों को भुगतान गैर-प्रत्यावर्तन के आधार पर किया जाएगा।

• इस संशोधन को सब-रूल (8) के बाद रूल 14 में, प्रमुख रूल्स में सब-रूल (9) के रूप में जोड़ा गया है।

i. इस रूल के दायरे में सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS), महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (MSSC), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, किसान विकास पत्र (KVP) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत विभिन्न योजनाएं आती हैं।

ii. एक अन्य संशोधन खाताधारक की मृत्यु पर संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। पहले, इस परिवर्तन की अनुमति नहीं थी और अन्य प्रमुख संशोधनों में नाम/उपनाम में परिवर्तन, नाबालिगों के नाम पर खाते आदि शामिल हैं।

28. जुलाई 2023 में, अर्बन 20(U20) 2023 के चेयर सिटी अहमदाबाद (गुजरात) ने _____, गुजरात में 2-दिवसीय U20 मेयरल समिट 2023 की मेजबानी की।

- 1) सूरत
- 2) गांधीनगर
- 3) राजकोट
- 4) जूनागढ़

5)पोरबंदर

उत्तर- 2)गांधीनगर

स्पष्टीकरण:

अर्बन 20(U20) 2023 के चेयर सिटी अहमदाबाद (गुजरात) ने 7 से 8 जुलाई 2023 तक गांधीनगर, गुजरात में 2 दिवसीय U20 मेयरल समिट 2023 की मेजबानी की। समिट का समापन महापौरों द्वारा G20 नेताओं को विज्ञप्ति सौंपने के साथ हुआ।

i.अहमदाबाद के मेयर किरीटकुमार J परमार ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और G20 (ग्रुप ऑफ़ 20) शेरपा अमिताभ कांत को विज्ञप्ति सौंपी।

ii.हैंडओवर का संचालन U20 संयोजकों, C40 सिटीज़ और यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट्स (UCLG) द्वारा किया गया था।

29. जुलाई 2023 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि _____ (राज्य) में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को भारत सरकार द्वारा 'अनुसूची B' से 'अनुसूची A' श्रेणी के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSE) में पदोन्नत किया गया है।

1)त्रिपुरा

2)नागालैंड

3)मिजोरम

4)मेघालय

5)असम

उत्तर-5)असम

स्पष्टीकरण:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनी हालिया अधिसूचना में घोषणा की कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को भारत सरकार द्वारा 'अनुसूची B' से 'अनुसूची A' श्रेणी के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSE) में पदोन्नत किया गया है।

i.'अनुसूची A' उद्यम के रूप में अपनी नई स्थिति के साथ, NRL प्रतिष्ठित नवरत्न प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है। एक नवरत्न कंपनी के रूप में, NRL को केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना 1,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की स्वतंत्रता होगी।

ii.NRL के पास अब संयुक्त उद्यमों, रणनीतिक साझेदारी और विशेष प्रयोजन वाहनों के संबंध में तेजी से निर्णय लेने का अधिकार होगा, जिससे रणनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

30. डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलिकम्युनिकेशन्स के साथ GoI के निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में (जुलाई'23 में) इंटरनेट की परिवर्तनकारी भूमिका का जश्न मनाने के लिए "भारत इंटरनेट उत्सव" लॉन्च किया है?

1)UMANG

2)MyGov

3)ईपाठशाला

4)डिजीलॉकर

5)PMO इंडिया

उत्तर- 2)MyGov

स्पष्टीकरण:

मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्प्युनिकेशन (MoC) के तहत डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलिकम्युनिकेशन्स (DoT) ने MyGov (भारत सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच) के सहयोग से नागरिकों को अपनी कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके इंटरनेट की परिवर्तनकारी भूमिका का जश्न मनाने के लिए "भारत इंटरनेट उत्सव" लॉन्च किया है कि कैसे इंटरनेट ने उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

i.इस उत्सव में भाग लेने के लिए, नागरिक अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन पर विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों के 2 मिनट तक के वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर #BharatInternetUtsav या अपलोड इन ड्राइव लिंक के साथ साझा कर सकते हैं, और यही लिंक MyGov पर <https://innovateindia.mygov.in/bharat-internet-utsav/> पर जमा किया जा सकता है।

ii.प्रतियोगिता 07.07.2023 से 21.08.2023 तक MYGOV पर आयोजित की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ कहानियों को 15,000 रुपये तक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।

31. हाल ही में (जुलाई 2023 में) किस कंपनी ने अटल टिकरिंग लैब्स (ATL) के तहत एक उद्योग यात्रा पहल शुरू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के साथ सहयोग किया है?

- 1) ल्यूपिन लिमिटेड
- 2) सिप्ला लिमिटेड
- 3) बायर
- 4) अल्केम लैबोरेट्रीज
- 5) सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

उत्तर-3) बायर

स्पष्टीकरण:

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने बायर के सहयोग से गुजरात के वापी में बायर की विनिर्माण सुविधा में अटल टिकरिंग लैब्स (ATL) के तहत एक उद्योग यात्रा पहल शुरू की।

i. सहयोग का उद्देश्य छात्रों को उद्योग में उपयोग की जाने वाली नवीनतम विनिर्माण तकनीकों और प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना है।

ii. बायर ने ATL छात्रों के लिए वापी (गुजरात), शमीरपेट (हैदराबाद), चंदिप्या (तेलंगाना) और बेंगलूर में अपने विनिर्माण और उत्पादन संयंत्र और अनुसंधान केंद्र खोले हैं ताकि वे अनुभव कर सकें कि उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी, स्वचालन और नवाचार का लाभ कैसे उठाया जाता है।

32. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अतिरिक्त सचिव भुवनेश कुमार ने हाल ही में (जुलाई '23 में) किस शहर में उत्पाद डिजाइन केंद्र (PDC) का उद्घाटन किया है?

- 1) मुंबई, महाराष्ट्र
- 2) अहमदाबाद, गुजरात
- 3) नई दिल्ली, दिल्ली
- 4) कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- 5) नोएडा, उत्तर प्रदेश

उत्तर-4) कोलकाता, पश्चिम बंगाल

स्पष्टीकरण:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अतिरिक्त सचिव भुवनेश कुमार ने उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC), कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित उत्पाद डिजाइन केंद्र (PDC) का उद्घाटन किया।

- इस अवसर पर 'कृषि और पर्यावरण (AgriEnIcs) में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली, दिल्ली के तहत विकसित दालों के लिए मशीन विजन तकनीक के माध्यम से एक उपस्थिति आधारित पहचान प्रणाली 'ग्रेन-एक्स' भी लॉन्च की गई।

i. उत्पाद डिजाइन केंद्र (PDC): यह केंद्र सिस्टम डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, विचार और निर्माण के लिए सभी सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है।

ii. 'ग्रेन-एक्स': यह 14 प्रकार की दालों के लिए उपस्थिति-आधारित इलेक्ट्रॉनिक (e)-गुणवत्ता पहचान प्रणाली है।

33. जुलाई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 50वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) सैक पेलेट्स पर GST, अर्ध-तैयार घटक जो सैकिंग उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है।

B) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST छूट है।

C) कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की एक समान कर दर लागू की जाएगी।

- 1) केवल A
- 2) केवल A & B
- 3) केवल B & C
- 4) केवल A & C
- 5) सभी A, B & C

उत्तर-3) केवल B & C

स्पष्टीकरण:

11 जुलाई, 2023 को, वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 50वीं बैठक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित की गई थी।

i. GST काउंसिल की 50वीं बैठक के मील के पथर को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (अध्यक्ष) ने काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति में 'GST काउंसिल- 50 स्टेप्स टुवार्ड्स ए जर्नी' शीर्षक से एक लघु वीडियो फिल्म जारी की।

ii. सैक पैलेट्स पर GST, अर्ध-तैयार घटक जो सैकिंग उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, वह 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसमें बिना पकाए, बिना तले हुए और बाहर निकाले गए सैक पैलेट शामिल हैं।

iii. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST छूट को निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समान सेवाओं तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. GST काउंसिल के अनुसार, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की एक समान कर दर लागू की जाएगी।

- कर कैसीनो के लिए खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य, घुड़दौड़ के लिए सट्टेबाजों/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव के पूरे मूल्य और ऑनलाइन गेमिंग के लिए लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर आधारित होगा।

34. जुलाई 2023 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा अधिसूचित नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT ने उपभोक्ताओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पीने योग्य पानी की बोतलों और फ्लेम-प्रोड्यूसिंग लाइटर पर 2 नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अधिसूचित किए हैं।

B) पीने योग्य पानी की बोतलों के लिए QCO तांबे, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बनी पीने योग्य पानी की बोतलों के उत्पादन और आयात के लिए उपयुक्त भारतीय मानक (IS) के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को अनिवार्य करता है।

C) 'फ्लेम-प्रोड्यूसिंग लाइटर' के लिए QCO घरेलू बाजार के लिए निर्मित या भारत में आयातित फ्लेम लाइटर के लिए 'लाइटर के लिए सुरक्षा विशिष्टता' और 'यूटिलिटी लाइटर के लिए सुरक्षा विशिष्टता' के लिए IS के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण अनिवार्य करता है।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

5 जुलाई 2023 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने उपभोक्ताओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पीने योग्य पानी की बोतलों और फ्लेम-प्रोड्यूसिंग लाइटर पर 2 नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अधिसूचित किए।

- फ्लेम - लाइटर उत्पादन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023

- पीने योग्य पानी की बोतलों (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023।

i. पीने योग्य पानी की बोतलों के लिए नया QCO: यह तांबे, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बनी पीने योग्य पानी की बोतलों के उत्पादन और आयात के लिए उपयुक्त भारतीय मानक (IS) के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को अनिवार्य करता है।

ii. फ्लेम-प्रोड्यूसिंग लाइटर के लिए नया QCO: यह घरेलू बाजार के लिए निर्मित या भारत में आयातित फ्लेम लाइटर के लिए 'लाइटर के लिए सुरक्षा विशिष्टता' और 'यूटिलिटी लाइटर के लिए सुरक्षा विशिष्टता' के लिए IS के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को अनिवार्य करता है। लाइटर दो प्रकार, फ्लेम और स्पार्क प्रकार के उपलब्ध हैं।

iii. नए मानक विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण के लिए एक गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेंगे और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी योगदान देंगे।

35. कौन सी कंपनी हाल ही में (जुलाई '23 में) मेसर्स इंटरसर्ट USA द्वारा रिश्वत-विरोधी प्रबंधन प्रणाली (ABMS) के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) बन गई है?

1) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन

2) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

3) कोल इंडिया लिमिटेड

4) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

5)स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
उत्तर-1)ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन
स्पष्टीकरण:

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), भारत में सबसे बड़ी कूड ऑयल और नेचुरल गैस महारत्न कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका(USA) में एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय, मेसर्स इंटरसर्ट USA द्वारा रिश्वत-रोधी प्रबंधन प्रणाली (ABMS) के लिए प्रमाणित होने वाली **भारत की पहली** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) बन गई है।

- ONGC के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरुण कुमार सिंह ने एक पुरस्कार समारोह में ABMS प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

36. जुलाई 2023 में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव, मनोज आहूजा ने कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत बैंकों के लिए BHARAT (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक से _____ के लिए एक नया अभियान शुरू किया।

- 1)प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में जानकारी प्रदान करें
- 2)बैंक से योजनाओं के गुलदस्ते के बारे में जानकारी प्रदान करें
- 3)बैंकों से धन जुटाना
- 4)फसलों को बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें
- 5)किसानों के लिए उपलब्ध संस्थागत ऋण से संबंधित जानकारी प्रदान करें।

उत्तर-3)बैंकों से धन जुटाना

स्पष्टीकरण:

12 जुलाई 2023 को, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के सचिव, मनोज आहूजा ने बैंकों से धन जुटाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत बैंकों के लिए **BHARAT** (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया।

- 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला 1 महीने का अभियान 7200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।

i.इस योजना को समर्थन देने वाले बैंकों ने 42,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ AIF के तहत 24750 करोड़ रुपये के ऋण के साथ 31,850 कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाई हैं।

ii.13 जुलाई 2023 को कृषि मंत्रालय ने बैंकों से कृषि क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के AIF को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

iii.इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जाना है और ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता वर्ष 2032-33 तक दी जाएगी।

37. भारत के पहले क्षेत्रीय बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यूज एंकर का नाम बताइए जिसे हाल ही में (जुलाई 23 में) ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड (OTV) द्वारा पेश किया गया था।

- 1)शालू
- 2)टीना
- 3)सारा
- 4)मानव
- 5)लीसा

उत्तर-5)लीसा

स्पष्टीकरण:

ओडिशा में एक ओडिया आधारित प्रसारण और डिजिटल मीडिया कंपनी, ओडिशा टेलीविज़न लिमिटेड (OTV) ने, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में भारत और ओडिशा की पहली क्षेत्रीय बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समाचार एंकर "लीसा" पेश की। AI लीसा की शुरुआत, OTV की दूरदर्शी टीम द्वारा संचालित एक पहल है।

i.लीसा फ्री-टू-एयर क्षेत्रीय टेलीविजन प्रसारण मंच में पहली AI एंकर है और उड़िया, अंग्रेजी और अन्य सहित कई भाषाएं बोलने की क्षमता वाली पहली ओडिया समाचार एंकर भी है।

38. उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ संशोधित प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (PMJAY-MA) योजना शुरू की है।

- 1) गुजरात
- 2) मध्य प्रदेश
- 3) झारखण्ड
- 4) महाराष्ट्र
- 5) आंध्र प्रदेश

उत्तर- 1) गुजरात

स्पष्टीकरण:

11 जुलाई 2023 को, गुजरात सरकार ने संशोधित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (PMJAY-MA) योजना शुरू की, जिसके तहत लोग 10 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं, जो कि 5 लाख रुपये की पिछली सीमा से दोगुनी वृद्धि है।

- संशोधित योजना को आधिकारिक तौर पर गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रुशिकेश पटेल ने गुजरात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च किया।

i. नई संशोधित PMJAY-MA योजना से गुजरात में लगभग 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्डधारकों को उच्च लागत वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलता है।

ii. PMJAY-MA के तहत, राज्य में 2027 सरकारी अस्पतालों, 803 निजी अस्पतालों और 18 केंद्र सरकार की सुविधाओं को उपचार की पेशकश करने या ऑपरेशन करने की अनुमति है, और इन अस्पतालों में कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए 2471 प्रकार के उपचार और सर्जरी उपलब्ध हैं।

39. जुलाई 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) ओडिशा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, त्वरित विकास के लिए उपाय करने और ओडिशा की जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और संरक्षित करने के लिए 'अमा ओडिशा नबिन ओडिशा' योजना को मंजूरी दी।

B) ओडिशा मंत्रिमंडल ने ओडिशा की सोरा जनजातियों को कई लाभ शामिल करने के लिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भतरी भाषा को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी।

C) ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना की अध्यक्षता में ओडिशा सरकार के 119वें स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी (SLSWCA) ने लगभग 3266 करोड़ रुपये की 11 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।

- 1) केवल A
- 2) केवल A & B
- 3) केवल B & C
- 4) केवल A & C
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- 4) केवल A & C

स्पष्टीकरण:

10 जुलाई 2023 को, मुख्यमंत्री (CM) नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, त्वरित विकास के लिए उपाय करने और जगन्नाथ संस्कृति और ओडिशा की परंपरा को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए 'अमा ओडिशा नबिन ओडिशा' योजना को मंजूरी दी।

योजना के तहत, 4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया जाएगा, और यह 50 लाख रुपये की पात्रता वाली सभी ग्राम पंचायतों (GP) को कवर करेगा।

i. ओडिशा मंत्रिमंडल ने ओडिशा की कंध जनजातियों को कई लाभ शामिल करने के लिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में **कुई भाषा** को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी।

ii. 10 जुलाई 2023 को, ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना की अध्यक्षता में ओडिशा सरकार के 119वें स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी (SLSWCA) ने लगभग 3266 करोड़ रुपये की 11 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।

- ये परियोजनाएं ओडिशा के बालासोर, बलांगीर, कालाहांडी, खोरधा और जाजपुर जिलों में स्थापित की जाएंगी और इनसे 9,146 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

40. उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई '23 में) सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 1) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- 2) भारतीय खाद्य निगम
- 3) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- 4) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
- 5) भारतीय मानक ब्यूरो

उत्तर- 4) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

स्पष्टीकरण:

रक्षा मंत्रालय (MoD) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और नई दिल्ली, दिल्ली में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- रक्षा मंत्रालय (MoD) की ओर से महानिदेशक (आपूर्ति और परिवहन) लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के CEO श्री G कमला वर्धन राव ने रक्षा मंत्री (MoD) राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (MoHFW) डॉ. मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में MoU पर हस्ताक्षर किए।
- i. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मनसुख मंडाविया ने श्री अन्ना (बाजरा) की खपत और इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए 'हेल्थ रेसिपिस फोर डिफेन्स' नामक पुस्तक का अनावरण किया।
- ii. यह पुस्तक MoD के तहत विभिन्न कैंटीनों और खाद्य दुकानों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगी।

41. हाल ही में (जुलाई '23 में) किस कंपनी ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के उन्नत संस्करण को विकसित करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं?

- 1) इंफोसिस लिमिटेड
- 2) विप्रो लिमिटेड
- 3) HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
- 4) टेक महिंद्रा
- 5) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

उत्तर- 5) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

स्पष्टीकरण:

भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने GeM मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली में GeM पोर्टल के विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए सरकारी खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

i. GeM पोर्टल को वाणिज्य मंत्रालय के तहत आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (DGS&D) द्वारा नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तकनीकी समर्थन के साथ विकसित किया गया था।

42. जुलाई 2023 में, संचार मंत्री (MoC) अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली, दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2023) के संस्करण के कर्टन रेजर का उद्घाटन किया।

- 1) 5वें
- 2) 7वें
- 3) 4वें
- 4) 6वें
- 5) 3वें

उत्तर - 2) 7वें

स्पष्टीकरण:

संचार मंत्री (MoC) अश्विनी वैष्णव ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2023) के 7 वें संस्करण के कर्टनरेजर का उद्घाटन किया।

i. संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) संयुक्त रूप से 'ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन' विषय के साथ एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के सातवें संस्करण की मेजबानी करेंगे, जो प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली में 27 से 29 अक्टूबर तक होने वाला है।

ii. इस आयोजन में 'भागीदार देशों और 'वर्चुअल एक्सहिबिशन' की अवधारणा पेश की जाएगी।

43. उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) ऑडिटऑनलाइन के एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मॉड्यूल का शुभारंभ किया है।

- 1) गृह मंत्रालय
 - 2) वित्त मंत्रालय
 - 3) पंचायती राज मंत्रालय
 - 4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - 5) कानून और न्याय मंत्रालय
- उत्तर - 3) पंचायती राज मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS), MoPR कपिल मोरेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ऑडिटऑनलाइन के एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मॉड्यूल को लॉन्च किया।

i. मॉड्यूल का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया के लिए एक अधिक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो ऑडिट निष्कर्षों के जवाब में किए गए कार्यों पर स्पष्टता सुनिश्चित करता है।

ii. ऑडिट ऑनलाइन का ATR मॉड्यूल पंचायतों को अधिक जवाबदेह, कुशल, सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनने में सक्षम बनाएगा, जिससे पूरे भारत में ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों का निर्बाध प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित होगा।

44. BSE लिमिटेड के अध्यक्ष S.S. मुंद्रा ने 10 जुलाई 2023 को अपने _____ स्थापना दिवस के उत्सव को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक नया लोगो लॉन्च किया है।

- 1) 149वां
- 2) 130वां
- 3) 150वां
- 4) 145वां
- 5) 120वां

उत्तर - 1) 149वां

स्पष्टीकरण:

10 जुलाई 2023 को, BSE लिमिटेड (जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था) के अध्यक्ष **S.S. मुंद्रा** ने BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल, मुंबई, महाराष्ट्र में अपने **149वें** स्थापना दिवस के उत्सव को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान BSE का नया लोगो लॉन्च किया।

i. BSE, 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित, एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज था।

ii. 1956 में, BSE प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 के तहत स्थायी मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया।

45. किस राज्य/UT ने हाल ही में (जुलाई'23 में) एक अलग प्रशासनिक विभाग के रूप में "लोक शिकायत विभाग" बनाया है?

- 1) मिजोरम
- 2) जम्मू & कश्मीर
- 3) हिमाचल प्रदेश
- 4) पुडुचेरी
- 5) त्रिपुरा

उत्तर - 2) जम्मू & कश्मीर

स्पष्टीकरण:

जम्मू & कश्मीर (J&K) सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में एक अलग प्रशासनिक विभाग के रूप में "**लोक शिकायत विभाग**" के निर्माण को मंजूरी दे दी, जो लोक शिकायतों के निवारण और उपराज्यपाल (LLG) मुलाक्रात - लाइव लोक शिकायत सुनवाई से भी निपटेगा।

i. यह J&K सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है जो ई-गवर्नेंस के माध्यम से शिकायत निवारण नवाचारों पर जोर देने के साथ नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना चाहती है।

ii. यह मंजूरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के संचालन की दूसरी अनुसूची के नियमों की प्रविष्टि 15 के अनुसरण में दी गई थी।

46. जुलाई 2023 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 महत्वपूर्ण खनिजों: लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, ज़िरकोनियम, नाइओबियम और टैंटलम के वाणिज्यिक खनन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) MMDR अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

B) यह प्रस्ताव भारत की 'परमाणु खनिज' सूची से छह खनिजों को हटा देगा और केंद्र को निजी खिलाड़ियों द्वारा खनन के लिए उनके भंडार की नीलामी करने का अधिकार देगा।

C) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) (OAMDR) अधिनियम, 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जो अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देता है।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 महत्वपूर्ण खनिजों: लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, ज़िरकोनियम, नाइओबियम और टैंटलम के वाणिज्यिक खनन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) MMDR अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

- नोट: 2014 के बाद से यह अधिनियम में 5वां संशोधन है। पहले के संशोधनों ने खनिजों के लिए ई-नीलामी को अधिकृत किया था और समाप्त हो रहे खदान पट्टों के विस्तार को सक्षम किया था।

i. यह प्रस्ताव भारत की 'परमाणु खनिज' सूची से छह खनिजों को हटा देगा और केंद्र को निजी खिलाड़ियों द्वारा खनन के लिए उनके भंडार की नीलामी करने का अधिकार देगा।

ii. संशोधन एक अन्वेषण लाइसेंस का प्रस्ताव करता है, जो किसी खनिज के लिए किसी विशेष भूमि की टोही (अन्वेषण) और पूर्वक्षण करने के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

iii. बड़े क्षेत्र के लिए अन्वेषण लाइसेंस एक ब्लॉक के लिए 5,000 sq km तक होगा। एक इकाई का कुल क्षेत्रफल 10,000 sq km से अधिक नहीं होगा।

iv. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) (OAMDR) अधिनियम, 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जो अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देता है।

47. जुलाई 2023 में, _____ चार रनवे और डुअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे (ECT) (एलिवेटेड टैक्सीवे) प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया।

1) नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

2) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,

3) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

4) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

5) केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

उत्तर - 3) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

स्पष्टीकरण:

14 जुलाई 2023 को, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा भी कहा जाता है, चार रनवे और डुअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे (ECT) (एलिवेटेड टैक्सीवे) प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया।

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, ज्योतिरादित्य M. सिंधिया ने IGIA, नई दिल्ली, दिल्ली में नए रनवे और ECT का उद्घाटन किया।
- 4,400 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले 4.4 km के रनवे का निर्माण एयर ट्रेफिक मूवमेंट्स (ATM) को संभालने के लिए किया गया था और वाइडबॉडी विमान प्रतिदिन 1,500 उड़ानों से 2,000 तक जाने के लिए तैयार है।
- ECT 2.1 किलोमीटर लंबी और 44 मीटर चौड़ी है, दोनों लेन के बीच 47 मीटर का अंतर है।
- टैक्सीवे उत्तरी और दक्षिणी हवाई क्षेत्रों को जोड़ देंगे और विमानों के लिए टैक्सी की दूरी 7 km कम कर देंगे और विमानों के लिए टैक्सी का समय 8-9 मिनट कम कर देंगे।

48. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ किस संगठन/कंपनी ने हाल ही में (जुलाई '23 में) भारत में पहाड़ी सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पांच दिशानिर्देश जारी किए हैं?

- 1) लार्सन & टुब्रो लिमिटेड
- 2) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी
- 3) H.G. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
- 4) टाटा प्रोजेक्ट्स
- 5) IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड

उत्तर-2) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

स्पष्टीकरण:

7 जुलाई 2023 को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की तकनीकी सहायता से MoRTH द्वारा विकसित भारत में पहाड़ी सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पांच दिशानिर्देश जारी किए।

i. ये दिशानिर्देश इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

ii. दिशानिर्देश सड़क नेटवर्क में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाली टिकाऊ सड़क परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

49. जुलाई 2023 में, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (MoS) राजीव चंद्रशेखर ने केरल के त्रिशूर में _____ (कंपनी) के साथ साझेदारी में देश के पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी (P3) मॉडल अटल टिकरिंग लैब (ATL) का उद्घाटन किया।

- 1) मोटोरोला
- 2) नोकिया
- 3) लावा
- 4) ओप्पो इंडिया
- 5) रियलमी

उत्तर-4) ओप्पो इंडिया

स्पष्टीकरण:

10 जुलाई 2023 को, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (MoS) राजीव चंद्रशेखर ने केरल के त्रिशूर में एक अग्रणी स्मार्टफोन विनिर्माण फर्म, **ओप्पो इंडिया** के साथ साझेदारी में NITI (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत देश के पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी (P3) मॉडल अटल टिकरिंग लैब (ATL) का उद्घाटन किया।

i. लर्निंग लिक्स फाउंडेशन, नई दिल्ली स्थित 'नॉट फॉर प्रॉफिट' संगठन कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा। ATL की स्थापना 6वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली बच्चों को नवीन समाधान विकसित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए की गई है।

ii. नवीन शिक्षण वातावरण बनाने के लिए 'हब एन स्पोक' रणनीति (एक वितरण नेटवर्क जो साइकिल के पहिये जैसा दिखता है) का पालन किया जाना चाहिए। नोडल स्कूल में ATL पड़ोसी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रयोग करने के लिए एक 'हब' के रूप में कार्य करेगा।

50. जुलाई 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मंत्रियों द्वारा प्रशासित _____ अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को अपराध से मुक्त करने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी।

- 1) 39
- 2) 14
- 3) 42
- 4) 34
- 5) 24

उत्तर-3) 42

स्पष्टीकरण:

12 जुलाई 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023** में संशोधन को मंजूरी दे दी। व्यापार और जीवन यापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 मंत्रियों द्वारा प्रशासित **42 अधिनियमों** में 183 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए संशोधन किए गए थे।

i. यह कृषि, पर्यावरण और मीडिया और प्रकाशन सहित कई क्षेत्रों में 42 कानूनों में संशोधन करता है।

ii. इसमें भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 शामिल हैं।

51. जुलाई 2023 में जारी NITI आयोग की रिपोर्ट 'नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI): ए प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023' का दूसरा संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "गलत" है/हैं?

A) भारत में मल्टीडायमेंशनली गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-2021 में 14.96% हो गई है।

B) बिहार में गरीबों यानी 1.43 करोड़ लोगों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

C) केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ दिल्ली, केरल, गोवा और तमिलनाडु में मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी का सामना करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है।

1) केवल A

2) केवल B

3) केवल C

4) केवल A & B

5) केवल B & C

उत्तर- 2) केवल B

स्पष्टीकरण:

17 जुलाई, 2023 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने NITI आयोग की रिपोर्ट 'नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI): ए प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023' का दूसरा संस्करण जारी किया।

- रिपोर्ट दो सर्वेक्षणों, नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे [NFHS-4 (2015-16)] और NFHS-5 (2019-21) के बीच मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी को कम करने में भारत की प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।
- भारत में मल्टीडायमेंशनली गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-2021 में 14.96% हो गई है।
- **उत्तर प्रदेश (UP) में गरीबों यानी 3.43 करोड़ लोगों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।**
- मल्टीडायमेंशनल गरीबों के अनुपात में सबसे तेज़ कमी UP, बिहार, मध्य प्रदेश (MP), ओडिशा और राजस्थान राज्यों में देखी गई।
- हालाँकि, बिहार, झारखंड, मेघालय, UP और MP (कमी के बाद भी) उस चार्ट में शीर्ष पर हैं जहाँ कुल आबादी का प्रतिशत मल्टीडायमेंशनली रूप से गरीब है।
- केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ दिल्ली, केरल, गोवा और तमिलनाडु में मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी का सामना करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है।

52. जुलाई 2023 में जारी IEA ऑयल 2023 - 2028 की आपूर्ति और मांग की गतिशीलता रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) रिपोर्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के प्रशासन के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा लॉन्च की गई थी।

B) ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक ऑयल मांग 2022 और 2028 के बीच 6% बढ़कर 105.7 मिलियन बैरल प्रति दिन (mb/d) तक पहुंच जाएगी।

C) FY 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 169 मिथाइलसाइक्लोपेंटाडिनेल मैंगनीज ट्राइकार्बोनाइल (MMT) थी।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर- 2) केवल A & B

स्पष्टीकरण:

17 जुलाई 2023 को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), पेरिस (फ्रांस) स्थित स्वायत्त संगठन, ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के प्रशासन के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC) के सहयोग से IEA ऑयल 2023-सप्लाय एंड

डीमांड डायनामिक्स टु 2028 शीर्षक वाली मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट ऑयल आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के लिए दिल्ली में लॉन्च किया।

i. ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट का अनुमान है कि मौजूदा सरकारी नीतियों और बाजार के रुझान के आधार पर, वैश्विक ऑयल मांग 2022 और 2028 के बीच 6% बढ़कर 105.7 मिलियन बैरल प्रति दिन (mb/d) तक पहुंच जाएगी।

- भारत की ऊर्जा की मांग किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ रही है और शहरीकरण और औद्योगीकरण द्वारा समर्थित अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण सभी क्षेत्रों में इसके बढ़ने की उम्मीद है।

ii. FY 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 223 मिथाइलसाइक्लोपेंटाडिनेल मैंगनीज ट्राइकार्बोनाइल (MMT) थी। पिछले वर्ष (FY 2021-22) की तुलना में विकास दर लगभग 12% थी।

53. जुलाई 2023 में जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI आयोग) की निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2022 के अनुसार, किस राज्य ने 80.89 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है?

- 1) तमिलनाडु
- 2) कर्नाटक
- 3) महाराष्ट्र
- 4) गुजरात
- 5) मध्य प्रदेश

उत्तर- 1) तमिलनाडु

स्पष्टीकरण:

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI आयोग) की रिपोर्ट के तीसरे संस्करण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2022 के अनुसार, तमिलनाडु ने 80.89 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

- महाराष्ट्र 78.20 के साथ दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 76.36 के साथ तीसरे स्थान पर और गुजरात 73.22 के साथ चौथे स्थान पर सभी श्रेणियों के राज्यों में EPI 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। EPI 2022 को NITI आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस (IFC) के सहयोग से तैयार किया था।
- हरियाणा (63.65), तेलंगाना (61.36) और उत्तर प्रदेश (61.23) भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं।
- हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड (59.13) शीर्ष पर है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा (51.58) शीर्ष पर है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (K&K), दिल्ली, अंडमान और निकोबार और लद्दाख हैं।
- तमिलनाडु के निर्यातक जिलों में कांचीपुरम, चेन्नई, तिरुपुर शीर्ष तीन हैं।

54. उस सरकारी एजेंसी/मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई '23 में) भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए टेक्नो-कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स (TCRM मैट्रिक्स) फ्रेमवर्क जारी किया है।

- 1) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
- 2) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- 3) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत
- 4) NITI आयोग
- 5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उत्तर- 4) NITI आयोग

स्पष्टीकरण:

NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने NITI वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत टेक्नो-कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स (TCRM मैट्रिक्स) फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसका शीर्षक है "A NEW LENS FOR INNOVATION IN NEW INDIA - इंटीग्रेटिव द टेक्नो-कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स", जिसका उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

i. फ्रेमवर्क एक अग्रणी मूल्यांकन उपकरण है जिसे भारत में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ii. TCRM मैट्रिक्स प्रौद्योगिकी मूल्यांकन ढांचे का ऐतिहासिक विकास प्रदान करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (TRL), व्यावसायीकरण तैयारी स्तर (CRL), और बाजार तैयारी स्तर (MRL) पैमाने शामिल हैं।

55. उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, "AI फॉर इंडिया 2.0" लॉन्च किया है।

- 1) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- 2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 3) गृह मंत्रालय
- 4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- 5) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

उत्तर- 1) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

विश्व युवा कौशल दिवस 2023 (15 जुलाई 2023) के अवसर पर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, "AI फॉर इंडिया 2.0" लॉन्च किया।

i. यह स्किल इंडिया और ग्रैब उर वर्नाक्युलर इंप्रिंट (GUVI), एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद, गुजरात इनक्यूबेटेड कंपनी की एक संयुक्त पहल है।

ii. MSDE और IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत यह राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVT) भारत के युवाओं को अग्रणी कौशल के साथ सक्षम बनाएगी।

56. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जुलाई'23 में) व्यक्तियों और परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक, 2023 पेश किया है?

- 1) गुजरात
- 2) महाराष्ट्र
- 3) राजस्थान
- 4) उत्तर प्रदेश
- 5) बिहार

उत्तर- 3) राजस्थान

स्पष्टीकरण:

18 जुलाई 2023 को, मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक, 2023 पेश किया, जिसका उद्देश्य राजस्थान के व्यक्तियों और परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

i. विधेयक 3 मुख्य क्षेत्रों जैसे न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार पर केंद्रित है।

ii. इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भारत सरकार के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), शिक्षा का अधिकार (RTE) और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे अधिकार-आधारित कानूनों के माध्यम से लागू किया गया था।

57. जुलाई 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (NITIE) को भारत के _____ IIM के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी।

- 1) 21वां
- 2) 22वां
- 3) 23वां
- 4) 24वां
- 5) 25वां

उत्तर- 1) 21वां

स्पष्टीकरण:

12 जुलाई 2023 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (NITIE) को 21वें भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के रूप में शामिल करने के लिए IIM अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी। संशोधन से NITIE मुंबई का नाम बदलकर IIM मुंबई कर दिया जाएगा।

- महाराष्ट्र दो IIM वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित IIM नागपुर और नव नामित IIM मुंबई शामिल हैं।
- स्वीकृत विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा, जो 20 जुलाई से 11 अगस्त, 2023 तक होने वाला है।

i. NITIE मुंबई की स्थापना 1963 में कुशल पेशेवर तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सहयोग से की गई थी।

ii. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2023 में NITIE को सातवां स्थान दिया गया।

58. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) का _____ स्थापना दिवस 12 जुलाई 2023 को मनाया गया।

1) 50वां

2) 25वां

3) 42वां

4) 35वां

5) 49वां

उत्तर- 3) 42वां

स्पष्टीकरण:

12 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। नई दिल्ली, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह थे।

i. इस दिन पूरे देश में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें "NABARD:42 इयर्स ऑफ़ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन" विषय पर एक वेबिनार भी शामिल था।

ii. वेबिनार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया, जिन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत के विकास में NABARD की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

59. जुलाई 2023 में भारतीय अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) 2023 की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी?

1) बेंगलुरु, कर्नाटक

2) मुंबई, महाराष्ट्र

3) नोएडा, उत्तर प्रदेश

4) गांधीनगर, गुजरात

5) इंदौर, मध्य प्रदेश

उत्तर- 4) गांधीनगर, गुजरात

स्पष्टीकरण:

17-18 जुलाई, 2023 को भारतीय अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) 2023 की बैठक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की।

i. यह FMCBG बैठक 14-15 जुलाई 2023 के दौरान गांधीनगर में तीसरी G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टीज (FCBD) बैठक से पहले हुई थी।

- G20 वित्त ट्रेक के परिणामों की समीक्षा करना और आगे बढ़ने के लिए मंत्रियों और राज्यपालों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है।
- G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IO) के प्रमुखों सहित 66 प्रतिनिधिमंडलों में 520 प्रतिभागी हैं।
- सदस्यों ने तीन वर्षों 2024-26 के लिए नई G20 2023 वित्तीय समावेशन कार्य योजना (FIAP) का भी समर्थन किया।
- बैठक के दौरान, इंडोनेशियाई वित्त मंत्री श्री मुल्यानी इद्रावती और उनकी भारतीय समकक्ष निर्मला सीतारमण ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से गांधीनगर, गुजरात में भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता (EFD) का उद्घाटन किया।
- तीसरी G20 FMCBG बैठक के दौरान हुई चर्चा नेताओं को सितंबर, 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सूचित करेगी। G20 FMCBG की अगली बैठक अक्टूबर 2023 में मराकेश, मोरक्को में 9 से 15 अक्टूबर, 2023 तक विश्व बैंक समूह (WBG) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की 2023 वार्षिक बैठक के मौके पर होगी।

60. भारत के साथ किस देश ने हाल ही में (जुलाई 23 में) "क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी: क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स" पर प्रस्तावों के लिए एक कॉल लॉन्च की है?

- 1) इंडोनेशिया
 - 2) यूनाइटेड किंगडम
 - 3) रूस
 - 4) जर्मनी
 - 5) संयुक्त राज्य अमेरिका
- उत्तर-5) संयुक्त राज्य अमेरिका

स्पष्टीकरण:

18 जुलाई 2023 को, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने संयुक्त रूप से "क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी: क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स" पर प्रस्तावों के लिए एक कॉल लॉन्च की। कार्यक्रम को इंडो-US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (IUSSTF) और USISTEF के सचिवालय द्वारा डिजाइन किया गया था।

i. इसका उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

ii. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और व्यावसायीकरण के लिए US-इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड (USISTEF) के तहत 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम शुरू किया गया और भारत में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) सुविधाओं को विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को प्रोत्साहित किया गया।

61. जुलाई 2023 में, केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 का एक प्रमुख प्रावधान लागू किया, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में महानिदेशक-DG (जांच) की नियुक्ति की शक्ति _____ (मंत्रालय) को देता है।

- 1) गृह मंत्रालय
- 2) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- 3) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
- 4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- 5) कानून और न्याय मंत्रालय

उत्तर-3) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 का एक प्रमुख प्रावधान लागू किया है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में महानिदेशक-DG (जांच) की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही, इसने DG की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति की संरचना को बदलने के लिए मौजूदा भर्ती नियमों प्रतिस्पर्धा CCI (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 को भी संशोधित किया है।

बदलाव क्या हैं?

- इससे पहले, खोज-सह-चयन समिति की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के सचिव करते थे। अब, CCI में शक्ति निहित होने पर, खोज-सह-चयन समिति की अध्यक्षता अब अध्यक्ष CCI द्वारा की जाएगी और इसमें दो सदस्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक को MCA और केंद्र सरकार (प्रतिष्ठित विशेषज्ञ-व्यक्ति) द्वारा नामित किया जाएगा।
- केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल (तीन नामों तक) में से CCI द्वारा DG की नियुक्ति की जाएगी।
- अभी तक DG की नियुक्ति का अधिकार MCA के पास था।

62. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जुलाई '23 में) राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है?

- 1) महाराष्ट्र
 - 2) गुजरात
 - 3) उत्तर प्रदेश
 - 4) मध्य प्रदेश
 - 5) केरल
- उत्तर- 2) गुजरात

स्पष्टीकरण:

20 जुलाई 2023 को, वाणिज्य & उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत एक पहल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम ने राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की।

- प्रोडक्ट टैगिंग और स्टोरी कार्ड लागू करने से सहयोग का उद्देश्य प्राप्त होगा।

i. ODOP-गुजरात 68 विशिष्ट प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें पारंपरिक शिल्प (जैसे गमथी ब्लॉक प्रिंट और माता-नी-पछेड़ी) से लेकर कृषि वस्तुओं (जैसे मूंगफली और जौरा) तक विविध रेंज शामिल है।

ii. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना एक पहल है जिसे एक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जाता है, जो हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक ले जाता है।

63. किस देश ने हाल ही में (जुलाई '23 में) सेमीकंडक्टर आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारी के लिए भारत के साथ सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- 1) जापान
- 2) चीन
- 3) ब्राज़ील
- 4) अर्जेंटीना
- 5) संयुक्त अरब अमीरात

उत्तर- 1) जापान

स्पष्टीकरण:

20 जुलाई 2023 को, भारत और जापान ने सरकार-से-सरकार और उद्योग-से-उद्योग सहयोग के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारी के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए।

i. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा ने नई दिल्ली, दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ii. MoC भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने में मदद करता है और जापानी तकनीक तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत को अपना सेमीकंडक्टर उद्योग विकसित करने में मदद मिलती है।

64. जुलाई 2023 में, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने पशुधन क्षेत्र के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की।

योजना के संचालन के लिए, DAHD ने _____ रुपये का एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है, जो पात्र क्रेडिट संस्थानों द्वारा MSME को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए 25% तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।

- 1) 320 करोड़
- 2) 750 करोड़
- 3) 540 करोड़
- 4) 620 करोड़
- 5) 450 करोड़

उत्तर- 2) 750 करोड़

उत्तर- 2) 750 करोड़

उत्तर- 2) 750 करोड़

उत्तर- 2) 750 करोड़

उत्तर- 2) 750 करोड़

स्पष्टीकरण:

20 जुलाई, 2023 को, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है।

i. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत योजना का उद्देश्य क्रेडिट वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट तक सुचारू पहुंच सुनिश्चित करना है।

ii. योजना को चालू करने के लिए, DAHD ने 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है जो पात्र क्रेडिट संस्थानों द्वारा MSME को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए 25% तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।

65. भारत सरकार के उस वैधानिक निकाय का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई '23 में) भारत में खाद्य सुरक्षा विश्लेषणात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए AOC INTERNATIONAL के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 1) भारतीय गुणवत्ता परिषद
- 2) भारतीय खाद्य निगम
- 3) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- 4) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
- 5) भारतीय मानक ब्यूरो

**उत्तर-4) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्पष्टीकरण:**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, और आधिकारिक विश्लेषणात्मक सहयोग एसोसिएशन(AOAC) INTERNATIONAL, एक वैश्विक संगठन जो खाद्य सुरक्षा, खाद्य अखंडता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाता है, ने भारत में खाद्य सुरक्षा विश्लेषणात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

i. MoU भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों और विश्लेषणात्मक प्रथाओं की उन्नति के लिए सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए FSSAI और AOAC दोनों की संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ii. इस सहयोग का उद्देश्य पूरे भारत में समान परीक्षण विधियों को बढ़ावा देना है, और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत विश्लेषणात्मक प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करना है।

iii. FSSAI को AOAC आधिकारिक तरीकों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जाएगी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण विधियों तक भारतीय खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की पहुंच साझा की जाएगी।

66. हाल ही में (जुलाई '23 में) किस मंत्रालय/कंपनी ने 2000 साल पुरानी प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण विधि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?

- 1) मिश्र धातु निगम लिमिटेड
- 2) गृह मंत्रालय
- 3) संस्कृति मंत्रालय
- 4) पर्यटन मंत्रालय
- 5) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

**उत्तर-3) संस्कृति मंत्रालय
स्पष्टीकरण:**

संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने 2000 साल पुरानी प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण विधि को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसे टैंकाई विधि के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में शेष पारंपरिक जहाज निर्माताओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाना और उनकी असाधारण शिल्प कौशल का प्रदर्शन करना है।

i. इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच समृद्ध समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करना और हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच सांस्कृतिक यादों को बढ़ावा देना भी है।

67. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जुलाई '23 में) नागरिकों को EV की खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है?

- 1) गुजरात
- 2) महाराष्ट्र
- 3) उत्तर प्रदेश
- 4) मध्य प्रदेश
- 5) ओडिशा

**उत्तर-3) उत्तर प्रदेश
स्पष्टीकरण:**

19 जुलाई 2023 को, उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने नागरिकों को UP में EV की खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन या EV) सब्सिडी पोर्टल (<https://upevsubsidy.in/>) लॉन्च किया। UP सरकार की नीति के अनुसार, खरीदार 14 अक्टूबर, 2022 के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए EV सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- i. पोर्टल के विकास और रखरखाव का काम **UPDESCO** (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को सौंपा गया है।
ii. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति, 2022 के तहत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को शर्तों के साथ लागू करने की अनुमति दी गई है। यह योजना 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी है।
iii. बैटरी के बिना EV खरीदने वाले खरीदारों के लिए सब्सिडी राशि कुल **सब्सिडी का 50%** होगी।

68. जुलाई 2023 में आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) भारत ने पहली बार गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, जिसका आयोजन भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा किया गया था।

B) केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने शिखर सम्मेलन में जारी खाद्य श्रेणी-वार मोनोग्राफ का एक संग्रह, फूड-ओ-कोपिया लॉन्च किया।

C) आम नियामक मंच 'SaNGRAH' - राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन: वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक को शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर-3) केवल B & C

स्पष्टीकरण:

पहली बार, भारत ने 20 से 21 जुलाई 2023 तक मानकेशॉ सेंटर, नई दिल्ली में समूह 20 (G20) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित **वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023** की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा किया गया था।

i. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने खाद्य मूल्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा प्रणालियों और नियामक ढांचे को मजबूत करने पर दृष्टिकोण का आदान-प्रदान करने के लिए खाद्य नियामकों का एक वैश्विक मंच बनाने के लिए वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया।

ii. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित नई पहलों की शुरुआत की।

- **फूड-ओ-कोपिया,** खाद्य श्रेणी-वार मोनोग्राफ का एक संग्रह शिखर सम्मेलन में जारी किया गया था।
- शिखर सम्मेलन में आम नियामक मंच 'SaNGRAH' - राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन: वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक भी लॉन्च किया गया।
- डैशबोर्ड एक सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT)-पोर्टल है जो नियमों, सूचनाओं, सावधानियों, दिशानिर्देशों, संदूषण सीमाओं और भारत के खाद्य नियामकों द्वारा नवीनतम प्रगति पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

69. जुलाई 2023 में, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) को _____ तक बढ़ा दिया।

1) 30 जून 2025

2) 30 जून 2024

3) 30 जून 2026

4) 30 जून 2027

5) 30 जून 2028

उत्तर- 2) 30 जून 2024

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत बेरोजगारी राहत योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) को दो साल के लिए **30 जून 2024** तक बढ़ा दिया है।

i. गजट अधिसूचना के अनुसार, इस योजना को पात्रता शर्तों में ढील और राहत की बढ़ी हुई दर के साथ 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

ii. इसकी स्थापना के बाद से यह तीसरा विस्तार है। इससे पहले, उन बीमित व्यक्तियों (IP) को राहत प्रदान करने के लिए इस योजना को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 और 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक दो बार बढ़ाया गया था, जो COVID-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए थे।

iii. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) योजना (पायलट आधार पर) शुरू की।

70. जुलाई 2023 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिन्हें संसदीय पैनल के सुझावों को शामिल करने के लिए फिर से काम किया गया था।

B) मध्यस्थता विधेयक में संशोधन जिसमें मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने की अधिकतम समयसीमा को 350 से घटाकर 120 दिन करना शामिल है।

C) प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (PRB) अधिनियम 1867 की जगह लेगा, जो भारत में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर- 4) केवल A & C

स्पष्टीकरण:

19 जुलाई 2023 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख विधेयकों: प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी, जिन्हें एक संसदीय पैनल के सुझावों को शामिल करने के लिए फिर से काम किया गया था।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए गए संशोधन काफी हद तक संसदीय पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं।
- ये बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे।

i. मध्यस्थता विधेयक में संशोधन जिसमें मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने की अधिकतम समयसीमा को 360 से घटाकर 180 दिन करना शामिल है।

- मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य के स्थान पर स्वैच्छिक बना दिया गया है।

ii. प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (PRB) अधिनियम 1867 की जगह लेगा, जो भारत में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।

- यह उस कानून को सरल बनाएगा जो विभिन्न प्रावधानों को अपराधमुक्त करता है और डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाता है।

71. जुलाई 2023 में NITI आयोग द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) NITI आयोग ने एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (IESS) 2047 (IESS 2047 V3.0) जारी किया।

B) IESS 2047 एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरैक्टिव टूल है जो मंत्रालयों/विभागों को नेट-शून्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य विकसित करने में मदद कर सकता है।

C) NITI आयोग ने ऊर्जा और जलवायु थिंक-टैंक वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से गोवा में 14वें स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM) के दौरान भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (ICED) 3.0 जारी किया।

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

20 जुलाई 2023 को, NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (IESS) 2047 (IESS 2047 V3.0) जारी किया।

i. IESS 2047 एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरैक्टिव टूल है जो मंत्रालयों/विभागों को नेट-शून्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य विकसित करने में मदद कर सकता है।

- ii. यह उपकरण ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का आकलन करके 2047 तक उत्सर्जन, लागत, भूमि और पानी की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह नेट-शून्य पथों के कई क्रमपरिवर्तन और संयोजन प्रदान करता है।
- iii. **NITI आयोग** ने ऊर्जा और जलवायु थिंक-टैंक **वसुधा फाउंडेशन** के सहयोग से गोवा में 14वें स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM) के दौरान भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (**ICED**) 3.0 जारी किया।
- iv. **ICED** ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटासेट पर संशोधित ऑनलाइन डेटा केंद्रों के लिए देश का वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।

72. हाल ही में (जुलाई 23 में) किस शहर को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब (CIH) मिला है जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा?

- 1) मुंबई, महाराष्ट्र
 - 2) अहमदाबाद, गुजरात
 - 3) कोच्चि, केरल
 - 4) चेन्नई, तमिलनाडु
 - 5) बेंगलुरु, कर्नाटक
- उत्तर-3) कोच्चि, केरल

स्पष्टीकरण:

केरल को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब (**CIH**) मिला, जो उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को प्रोत्साहित करके टिकाऊ और किफायती भवन सुविधाओं के आसपास नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

i. CIH को शेल्टरटेक समिट में लॉन्च किया गया था, जो आवास और निर्माण नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक समिट था, जिसे चेन्नई, तमिलनाडु में हैबिटेड फॉर ह्यूमैनिटी और केरल स्टार्ट-अप मिशन (**KSUM**) द्वारा आयोजित किया गया था।

ii. CIH के समग्र कार्यक्रम प्रबंधन का ध्यान KSUM द्वारा किया जाएगा, और CIH कोच्चि, केरल में स्थित होगा, जो KSUM का मुख्यालय भी है।

73. किस कंपनी ने हाल ही में (जुलाई 23 में) 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक त्रि-सर्विसेज ऑल वुमेन मोटोसाइकल रैली - 'नारी सशक्तीकरण मोटरसाइकिल रैली' शुरू करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है?

- 1) TVS मोटर्स
 - 2) बजाज ऑटो
 - 3) हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
 - 4) रॉयल एनफील्ड इंडिया
 - 5) ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
- उत्तर- 1) TVS मोटर्स

स्पष्टीकरण:

भारतीय सेना ने **TVS मोटर्स** कंपनी के साथ साझेदारी में 24वें कारगिल विजय दिवस मनाने और महिलाओं की बहादुर भावना को उजागर करने के लिए एक त्रि-सर्विसेज ऑल वुमेन मोटोसाइकल रैली - 'नारी सशक्तीकरण मोटरसाइकिल रैली' शुरू की। थल सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल मनोज पांडे ने 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली से सभी महिला मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई।

i. कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है।

74. विश्व आर्थिक मंच (WEF) के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जुलाई 23 में) 'सागु बागू' (कृषि उन्नति) परियोजना चरण 1 अंतर्दृष्टि रिपोर्ट लॉन्च की है?

- 1) महाराष्ट्र
 - 2) आंध्र प्रदेश
 - 3) कर्नाटक
 - 4) तेलंगाना
 - 5) पश्चिम बंगाल
- उत्तर-4) तेलंगाना

स्पष्टीकरण:

20 जुलाई 2023 को, तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने तेलंगाना, हैदराबाद में 'सागु बागू' (कृषि उन्नति) परियोजना चरण 1 अंतर्दृष्टि रिपोर्ट लॉन्च की। परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना में किसानों को AI-आधारित कृषि तकनीक सेवाएं प्रदान करना है।

i. WEF रिपोर्ट कृषि नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI4AI) के माध्यम से शुरू किए गए पायलट परियोजना के सफल कार्यान्वयन को दर्शाती है, जिससे तेलंगाना के खम्मम जिले में 7,000 से अधिक मिर्च किसानों को लाभ हुआ है।

- AI4AI- तेलंगाना सरकार और WEF के बीच एक सहयोग पहल है।

ii. यह परियोजना 2022 में शुरू की गई थी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के समर्थन से डिजिटल ग्रीन (तीन एग्रीटेक स्टार्टअप के साथ कंसोर्टियम में) द्वारा कार्यान्वित की गई है।

75. जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त नहीं किया गया है?

- 1) सुलता देव
- 2) PT उषा
- 3) कर्णम मल्लेश्वरी
- 4) फांगनोन कोन्याक
- 5) फौजिया खान

उत्तर-3) कर्णम मल्लेश्वरी

स्पष्टीकरण:

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सांसदों पिलावुल्लाकांडी थेक्केपरांबिल उषा (PT उषा), फांगनोन कोन्याक, फौजिया खान और सुलता देव को उपाध्यक्ष के पैनल में नियुक्त किया।

- उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन 17 जुलाई 2023 से किया गया है। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें से आधे (4) महिलाएं हैं।
- भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के इतिहास में पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- इन 4 महिला सदस्यों के अलावा, V विजयसाई रेड्डी (आंध्र प्रदेश), घनश्याम तिवारी (राजस्थान), डॉ L हनुमंथैया (कर्नाटक), सुखेंदु शेखर राय (पश्चिम बंगाल) को भी पैनल में नामित किया गया है।
- नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक, उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित होने वाली नागालैंड की पहली महिला बनीं।
- वह राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली नागालैंड की पहली महिला और संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली नागालैंड की दूसरी महिला हैं।
- PT उषा राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित होने वाली पहली नामांकित MP बनीं।

76. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जुलाई '23 में) गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक 2023 पेश किया है?

- 1) झारखंड
- 2) महाराष्ट्र
- 3) राजस्थान
- 4) गुजरात
- 5) उत्तर प्रदेश

उत्तर-3) राजस्थान

स्पष्टीकरण:

21 जुलाई 2023 को, राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक 'राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023' पेश किया।

i. एग्रीगेटर्स, जिनमें खाद्य वितरण ऐप और ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं, को अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ दिनों के भीतर राजस्थान सरकार को उनके साथ जुड़े या पंजीकृत सभी प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों का डेटाबेस प्रदान करना होगा।

77. उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में (जुलाई 23 में) XR स्टार्टअप प्रोग्राम में शामिल हुई है, जो मेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब (MSH) के बीच एक पहल है।

- 1) HCL टेक्नोलॉजी
 - 2) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
 - 3) इन्फोसिस लिमिटेड
 - 4) टेक महिंद्रा
 - 5) विप्रो लिमिटेड
- उत्तर- 1) HCL टेक्नोलॉजी

स्पष्टीकरण:

नोएडा, उत्तर प्रदेश में HCL टेक्नोलॉजी (HCL टेक) XR स्टार्टअप प्रोग्राम में शामिल हो गई है, जो मेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब (MSH) के बीच भारत में एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की खोज, पोषण और तेजी लाने के लिए एक पहल है।

i. इन स्टार्ट-अप्स को HCL टेक पेशेवरों द्वारा नेतृत्व प्रशिक्षण और व्यापार और उद्योग के दृष्टिकोण को साझा करने के माध्यम से सलाह दी जाएगी।

ii. सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया XR स्टार्टअप प्रोग्राम, MeitY स्टार्टअप हब (MSH) और मेटा के बीच एक संयुक्त प्रयास है।

iii. XR प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले चयनित स्टार्टअप को HCL टेक से 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है।

78. जुलाई 2023 में, _____ (राज्य/UT) में काउन्सिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (CSIR-IIIM) का "कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट" कनाडा स्थित कंपनी इंडसकैन लिमिटेड के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत भारत में अपनी तरह की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है।

- 1) उत्तर प्रदेश
 - 2) महाराष्ट्र
 - 3) दिल्ली
 - 4) जम्मू और कश्मीर
 - 5) गुजरात
- उत्तर- 4) जम्मू-कश्मीर

स्पष्टीकरण:

जम्मू, जम्मू & कश्मीर (J&K) में काउन्सिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (CSIR-IIIM) की कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट इंडसकैन लिमिटेड के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत भारत में अपनी तरह की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, जिसका मुख्यालय टोरंटो, कनाडा में है।

i. यह प्रोजेक्ट CSIR-IIIM और कनाडा स्थित इंडसकैन के बीच एक वैज्ञानिक समझौते के तहत चल रही है।

ii. यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

iii. मंत्री ने संस्थान के संरक्षित क्षेत्र में कैनबिस की खेती के तरीकों और इस महत्वपूर्ण पौधे पर किए जा रहे शोध कार्य के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए CSIR-IIIM के कैनबिस खेती फार्म का दौरा किया।

iv. यह भारत में कैनबिस की खेती के लिए पहला लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला संस्थान है।

79. जुलाई 2023 में श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) यात्रा के दौरान, भारत और श्रीलंका ने भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए "प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, केटलाइसिंग प्रोस्पेरिटी" शीर्षक से एक विज्ञान दस्तावेज़ अपनाया।

B) 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

C) भारतीय प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर एक नेटवर्क-टू-नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

1)केवल A

2)केवल A & B

3)केवल B & C

4)केवल A & C

5)सभी A, B & C

उत्तर -5)सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20-21 जुलाई 2023 तक भारत की आधिकारिक दो दिवसीय यात्रा की। उनका स्वागत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) V मुरलीधरन ने किया। जुलाई 2022 में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह विक्रमसिंघे की पहली भारत यात्रा है।

- यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देश 2023 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
- यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
- भारत और श्रीलंका ने "प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, केटलाइसिंग प्रोस्पेरिटी" शीर्षक से एक विज्ञान दस्तावेज़ अपनाया, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
- MoU श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर है।
- समपुर सौर ऊर्जा परियोजना और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) बुनियादी ढांचे में तेजी लाना हरित हाइड्रोजन का पता लगाना है।
- 21 जुलाई 2023 को, भारतीय प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर एक नेटवर्क-टू-नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- NIPL और लंका पे के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेनदेन के लिए UPI-आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो निर्बाध और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देता है।
- नोट: श्रीलंका भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति और SAGAR (सिक्वोरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन) दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

80. जुलाई 2023 में भारत और बांग्लादेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) भारत और बांग्लादेश ने रेल भवन, ढाका, बांग्लादेश में ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेल लाइन के लिए कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

B) यह परियोजना भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LoC) के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

C) बांग्लादेश रेलवे (BR) ने ढाका से टोंगी तक निर्माणाधीन तीसरे और चौथे दोहरे गेज रेल ट्रैक और टोंगी से जॉयदेबपुर तक डबल-लाइन दोहरी गेज के लिए सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए L&T इंग्रस्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को नियुक्त किया है।

1)केवल A

2)केवल A & B

3)केवल B & C

4)केवल A & C

5)सभी A, B & C

उत्तर- 2)केवल A & B

स्पष्टीकरण:

23 जुलाई, 2023 को, भारत और बांग्लादेश ने रेल भवन, ढाका, बांग्लादेश में ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेल लाइन के लिए कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

i. यह परियोजना भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LoC) के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

ii. बांग्लादेश रेलवे (BR) ने ढाका से टोंगी तक निर्माणाधीन तीसरे और चौथे दोहरे गेज रेल ट्रैक और टोंगी से जॉयदेबपुर तक डबल-लाइन दोहरी गेज के लिए सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र स्थित भारतीय कंपनी, **KEC इंटरनेशनल लिमिटेड** को नियुक्त किया है।

- यह Tk (बांग्लादेशी टका) 3.49 बिलियन का अनुबंध है।

81. किस राज्य की ऑथूर वेट्टिलाई (ऑथूर बेटल लीव्स) को हाल ही में (जुलाई'23 में) भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है?

- 1)आंध्र प्रदेश
- 2)तमिलनाडु
- 3)केरल
- 4)कर्नाटक
- 5)तेलंगाना

उत्तर- 2)तमिलनाडु

स्पष्टीकरण:

भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने थूथुकुडी जिला प्रशासन को तमिलनाडु के **ऑथूर वेट्टिलाई** (ऑथूर बेटल लीव्स) का भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रमाण पत्र जारी किया है।

i. तमिलनाडु (TN) के थूथुकुडी जिले के औथूर गांव में खेती की जाने वाली सुपारी, जिसे स्थानीय रूप से तमिल में वेट्टिलाई के नाम से जाना जाता है, ने अप्रैल 2023 में GI टैग प्राप्त किया।

ii. टैग की सुविधा तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और NABARD (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) मदुरै एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन फोरम (MABIF) द्वारा की गई थी और इसे लेखक वट्टारा वेत्रिलई विवासयिगल संगम के नाम से पंजीकृत किया गया था।

नोट- वेत्रिलई के अन्य नाम संस्कृत में ताम्बुलम, हिंदी में पान, तेलुगु में तमुला पाकुकिल्ली हैं।

82. जुलाई 2023 में, भारत सरकार (GoI) ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 (FY23) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों पर _____ की वार्षिक ब्याज दर निर्धारित करने को मंजूरी दी।

- 1)7.50%
- 2)8.20%
- 3)8.15%
- 4)7.90%
- 5)8.10%

उत्तर-3)8.15%

स्पष्टीकरण:

24 जुलाई 2023 को, **वित्त मंत्रालय**, भारत सरकार (GoI) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2022-2023 (FY23) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों पर **8.15%** की वार्षिक ब्याज दर निर्धारित करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।

- इस कदम से EPFO के 6 करोड़ से अधिक ग्राहक कवर होंगे।
- वर्तमान दर FY22 की तुलना में **0.05%** अधिक है जब यह 8.10% थी।

i. श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoL&E) ने EPF योजना, 1952 के पैरा 60 के तहत प्रावधानों के अनुसार EPF योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में ब्याज जमा करके EPF योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत केंद्र सरकार की इस मंजूरी से अवगत कराया है।

83. जुलाई 2023 तक, किस विश्वविद्यालय/संस्थान में मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) स्थापित किया जाएगा?

- 1) केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
- 2) केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय
- 3) कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय
- 4) केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान
- 5) मत्स्य पालन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान

उत्तर-2) केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय

स्पष्टीकरण:

मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमशीलता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केरल के कोच्चि में केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (KUFOS) में स्थापित किया जाएगा।

i. KUFOS को विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन AIC स्थापित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग से 10 करोड़ रुपये का अनुदान मिला।

- KUFOS, KUFOS के मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख, राधिका राजश्री SR के मार्गदर्शन में अपने प्रमुख अन्वेषक के रूप में इस परियोजना का नेतृत्व करेगा।
- KUFOS को मत्स्य पालन और समुद्री अध्ययन से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान और आउटरीच में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है।
- AIC पहल 2016 में स्थापित NITI आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

84. जुलाई 2023 में, भारत सरकार (GoI) ने दूरसंचार बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और पेटेंट को संभालने के लिए _____ को नोडल सुविधा एजेंसी बनाने का निर्णय लिया।

- 1) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
- 2) उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र
- 3) इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र
- 4) टेलीमैटिक्स विकास केंद्र
- 5) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

उत्तर-4) टेलीमैटिक्स विकास केंद्र

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार (GoI) ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) को दूरसंचार बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और पेटेंट को संभालने के लिए नोडल सुविधा एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है।

i. CDoT केवल SEP वार्ता के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा और किसी भी पक्ष के प्रति उसकी कोई वित्तीय देनदारी या दायित्व नहीं होगा।

ii. C-DoT स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और अनुसंधान संस्थाओं को उनके नवाचारों को IPR में बदलने और अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

85. जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

- A) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में 5वें हेलीकॉप्टर और स्माल एयरक्राफ्ट समिट (हेली समिट 2023) का उद्घाटन किया।
- B) ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोटे विमानों (22 मार्गों को पुरस्कृत करके) और हेलीकॉप्टरों के लिए (VGF बढ़ाकर और किराया सीमा को कम करके) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) 5.2 (RCS UDAN 5.2) भी लॉन्च की लॉन्च किया है।
- C) डिजिटल इंडिया के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल द्वारा हेलीसेवा एक एकल विंडो सेवा मंच है, जिसे हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर एक साझा मंच विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था।

1)केवल A

2)केवल A & B

3)केवल B & C

4)केवल A & C

5)सभी A, B & C

उत्तर- 5)सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में 5वें हेलीकॉप्टर और स्माल एयरक्राफ्ट समिट (हेली समिट 2023)का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) 5.2 (RCS उड़ान 5.2)और हेलीसेवा ऐप लॉन्च किया।

- हेली समिट का विषय "रीचिंग द लास्ट मील: रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स & स्माल एयरक्राफ्ट" था।
- समिट का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के सहयोग से किया गया था।
- छोटे विमानों के लिए (22 मार्ग आवंटित करके) और हेलीकॉप्टरों के लिए (VGF बढ़ाकर और किराया सीमा कम करके) **UDAN 5.2** लॉन्च किया गया है।
- हेलीसेवा डिजिटल इंडिया के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल द्वारा हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर एक साझा मंच विकसित करने के लिए एक एकल खिड़की सेवा मंच है।
- पवन हंस लिमिटेड और जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच भारत में हेलीकॉप्टर और छोटे विमान क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

86. जुलाई 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IBM इंडिया के सहयोग से राष्ट्रपति भवन द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम गैलरी 'मानव' का उद्घाटन किया।

B) भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के निर्माण में विभिन्न आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और योगदान को प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी 'जनजातीय दर्पण' का भी उद्घाटन किया।

C) राष्ट्रपति ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली, दिल्ली के खेल मैदान में एक क्रिकेट पवेलियन के निर्माण की आधारशिला रखी।

1)केवल A

2)केवल A & B

3)केवल B & C

4)केवल A & C

5)सभी A, B & C

उत्तर-3)केवल B & C

स्पष्टीकरण:

25 जुलाई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यालय में एक वर्ष पूरा किया। इस अवसर पर, उन्होंने नई दिल्ली, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

- अपने राष्ट्रपति पद के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने राष्ट्रपति पद के पिछले वर्ष की झलकियों के एक ई-पुस्तक संकलन के साथ, भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की पुनर्विकसित वेबसाइट लॉन्च की।
- उन्हें आयुष वेलनेस सेंटर, राष्ट्रपति संपदा पर पुस्तक की पहली प्रति भी मिली, जिसका शीर्षक (प्रिजर्विंग हेल्थ, एम्बॉसिंग ट्रेडिशन) था
- राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली, दिल्ली में शिव मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली, दिल्ली के खेल मैदान में एक क्रिकेट पवेलियन के निर्माण की आधारशिला रखी।
- इंटेल इंडिया के सहयोग से राष्ट्रपति भवन द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम गैलरी 'नवाचार' का उद्घाटन किया गया।
- राष्ट्रपति भवन के वस्त्र संग्रह 'सूत्र-कला दर्पण' का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्राचीन वस्त्र शामिल हैं जो इमारत की शानदार विरासत का दस्तावेजीकरण करते हैं।
- राष्ट्र निर्माण में विभिन्न आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और योगदान को प्रदर्शित करने वाली गैलरी 'जनजातीय दर्पण' का उद्घाटन किया। गैलरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) (संस्कृति मंत्रालय के तहत), नई दिल्ली, दिल्ली के सहयोग से विभिन्न विषयों और कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है।

87. जुलाई 2023 में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA & FW) ने _____ (योजना) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत 3 तकनीकी पहल YES-Tech, WINDS पोर्टल और AIDE (सहायक) मोबाइल ऐप लॉन्च की।

- 1)प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
- 2)प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- 3)प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- 4)प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- 5)प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

उत्तर-3)प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

स्पष्टीकरण:

21 जुलाई 2023 को, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA & FW) ने नई दिल्ली, दिल्ली में किसानों को सशक्त बनाने और उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत 3 तकनीकी पहल शुरू की।

i.केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरिन रिजिजू ने 2023-25 के वर्तमान निविदा चक्र से प्रभावी किसानों को सटीक मौसम डेटा, उपज अनुमान और फसल बीमा पहुंच प्रदान करने के लिए YES-Tech (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) मैनुअल, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल और AIDE (सहायक) मोबाइल ऐप सहित नई पहलों का शुभारंभ किया।

88. जुलाई 2023 तक रूरल WASH पार्टनर्स फोरम (RWPF) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

- A) जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) के एक मंच, रूरल WASH पार्टनर्स फोरम (RWPF) ने नई दिल्ली में RWPF पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनी पहली वर्षगांठ मनाई।
- B)कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन योजना (DMP) के लिए मैनुअल जारी किया।

C) पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) और टीच फॉर इंडिया, एक गैर-लाभकारी संगठन ने JJM डिजिटल एकेडमी की स्थापना के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।

- 1)केवल A
- 2)केवल A & B
- 3)केवल B & C
- 4)केवल A & C
- 5)सभी A, B & C

उत्तर- 2)केवल A & B

स्पष्टीकरण:

जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) का एक मंच, ग्रामीण WASH पार्टनर्स फोरम (RWPF) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली, दिल्ली में [रूरल WASH पार्टनर्स फोरम](#) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनी पहली वर्षगांठ मनाई।

- सम्मेलन का विषय "एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए स्वच्छ सुजल भारत" था।
- सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री ने किया। गजेन्द्र सिंह और विभिन्न पहल शुरू कीं जैसे
- कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आपदा प्रबंधन योजना (DMP) के लिए मैनुअल जारी किया।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर हितधारकों को शामिल करते हुए जल, स्वच्छता और सफाई (WASH) संपत्तियों और सेवाओं की सुरक्षा, निर्बाध आपूर्ति और न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा मैनुअल विकसित किया गया है।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) और एक गैर-लाभकारी संगठन एको इंडिया ने JJM डिजिटल एकेडमी की स्थापना के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए। JJM डिजिटल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा लॉन्च किया गया।

89. जुलाई 2023 में आयोजित 8वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (MI-8) और 14वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM-14) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) ऊर्जा मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 8वां मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (MI-8) और 14वां क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM-14) गोवा में आयोजित चौथे एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक के साथ हुआ।

B) वर्ष 2023 का विषय 'एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर' है और चौथी ETWG बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने की।

C) कार्यक्रम के दौरान, गोवा के मुख्यमंत्री (CM) प्रमोद सावंत ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित चार दिवसीय टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक प्रदर्शन शोकेस का उद्घाटन किया, जिसमें भारत और दुनिया भर में क्लीन एनर्जी में अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन किया गया।

- 1)केवल A
- 2)केवल A & B
- 3)केवल B & C
- 4)केवल A & C
- 5)सभी A, B & C

उत्तर -5)सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

ऊर्जा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 8वां मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (MI-8) और 14वां क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM-14) गोवा में 19 जुलाई 2023 से 22 जुलाई, 2023 तक आयोजित भारत के समूह 20 (G-20) की अध्यक्षता में चौथी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक के साथ हुआ।

- वर्ष 2023 का विषय 'एडवांसिंग क्लीन एनर्जी दुगेदर' है।
- इस कार्यक्रम में 34 सदस्य देशों ने भाग लिया। चौथी ETWG बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्रालय के सचिव **पंकज अग्रवाल** ने की।
- गोवा के मुख्यमंत्री (CM) प्रमोद सावंत ने **श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम** में आयोजित चार दिवसीय टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक प्रदर्शन का उद्घाटन किया, जिसमें भारत और दुनिया भर में क्लीन एनर्जी में अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन किया गया।
- ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (**EESL**) ने गोवा में हाल ही में संपन्न G20 हरित ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर 700 करोड़ रुपये के 15 समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- G20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री **राज कुमार सिंह** ने की।

90. जुलाई 2023 में, _____ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम (WCCF) का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया।

- 1) अहमदाबाद, गुजरात
 - 2) नई दिल्ली, दिल्ली
 - 3) बेंगलुरु, कर्नाटक
 - 4) चेन्नई, तमिलनाडु
 - 5) इंदौर, मध्य प्रदेश
- उत्तर-3) बेंगलुरु, कर्नाटक

स्पष्टीकरण:

कर्नाटक की राजधानी **बेंगलुरु** वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम (**WCCF**) का हिस्सा बनने वाला **पहला भारतीय शहर** बन गया, जो शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है।

- बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया और नेटवर्क में वर्तमान में छह महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। फोरम में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहर शामिल हैं।

i. अनबॉक्सिंग बैंगलोर नामक सहभागी परियोजना मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से बेंगलुरु के आसपास एक नई कहानी बनाने के लिए स्थापित की गई है और वे शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चर्चाओं का नेतृत्व कर रहे हैं।

ii. WCCF अनबॉक्सिंग BLR फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेगा, जो अप्रैल 2022 में एक्सेल इंडिया और फिलैंथ्रोपिस्ट के संस्थापक भागीदार प्रशांत प्रकाश और पत्रकार मालिनी गोयल द्वारा सह-स्थापित एक गैर-लाभकारी पहल है।

91. किस कंपनी ने हाल ही में (जुलाई '23 में) डाक विभाग के सहयोग से मिशन मिलेट पर एक विशेष डाक टिकट, एक अनुकूलित "माई स्टैम्प" जारी किया है?

- 1) हिन्दुस्तान यूनिवर्सिटी
- 2) ITC लिमिटेड
- 3) रिलायंस इंडस्ट्रीज
- 4) ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज
- 5) गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स

उत्तर- 2) ITC लिमिटेड

स्पष्टीकरण:

25 जुलाई 2023 को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित एक अग्रणी भारत बहु-व्यवसाय उद्यम **ITC लिमिटेड** ने संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (भारतीय डाक) के सहयोग से मिशन मिलेट पर एक विशेष डाक टिकट, एक अनुकूलित "माई स्टैम्प" जारी किया है।

i. श्री अन्न का जश्न मनाने और मिलेट्स के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डाक टिकट जारी किया गया था।

ii. डाक टिकट इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट्स 2023 के उपलक्ष्य में ITC के मिशन मिलेट्स पहल का एक हिस्सा है।

iii. विशिष्ट ITC मिशन मिलेट्स डाक टिकट किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और टिकाऊ खेती को पौष्टिक खाद्य उत्पादों और स्वादिष्ट मिलेट्स-आधारित व्यंजनों और व्यंजनों से जोड़ता है।

92. किस राज्य के विद्युत उत्पादन निगम ने 6,000 मेगावाट (MW) की कुल उत्पादन क्षमता के साथ पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजनाओं (PSPH) को लागू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (JV) बनाने के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) के साथ भागीदारी की?

- 1) ओडिशा
- 2) पश्चिम बंगाल
- 3) आंध्र प्रदेश
- 4) महाराष्ट्र
- 5) कर्नाटक

उत्तर-3) आंध्र प्रदेश

स्पष्टीकरण:

आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन (AP-जेनको) और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) आंध्र प्रदेश में 6,000 मेगावाट (MW) की कुल उत्पादन क्षमता के साथ पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स (PSPH) को लागू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (JV) बनाएंगे।

i. पहली परियोजना अल्लूरी सीतारामा राजू (ASR) जिले के GK वीथी मंडल के ऊपरी सिलेरू में 1,350 MW (9×150 MW) PSHP होगी। पूरा होने पर, सिलेरू बेसिन की संयुक्त स्थापित जलविद्युत क्षमता 2,425 MW से अधिक तक पहुंच जाएगी।

ii. कंपनियों को अभी भी मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर करना बाकी है और भागीदारों के पास बराबर (50:50) हिस्सेदारी होगी।

93. प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने हाल ही में (जुलाई '23 में) किस शहर में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी के लिए एक भविष्यवादी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र (IECC) कॉम्प्लेक्स, "भारत मंडपम" का उद्घाटन किया है?

- 1) बेंगलुरु, कर्नाटक
- 2) नई दिल्ली, दिल्ली
- 3) गांधीनगर, गुजरात
- 4) मुंबई, महाराष्ट्र
- 5) नोएडा, उत्तर प्रदेश

उत्तर-2) नई दिल्ली, दिल्ली

स्पष्टीकरण:

26 जुलाई 2023 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने एक भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र (IECC), पुनर्निर्मित भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) परिसर, जिसे प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया, और नई दिल्ली, दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण किया

- IECC कॉम्प्लेक्स का नाम "भारत मंडपम" रखा गया है और केंद्र का नामकरण समारोह एक ड्रोन का उपयोग करके किया गया था।
- PM मोदी ने नए ITPO अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र में हवन और पूजा की और केंद्र के निर्माण में शामिल श्रमिकों को सम्मानित किया।
- IECC कॉम्प्लेक्स G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है जो सितंबर 2023 में होने वाली है।
- IECC कॉम्प्लेक्स को 2,700 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया था, जिसका परिसर क्षेत्र 123 एकड़ है जो भारत का सबसे बड़ा MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ) गंतव्य है।

94. जुलाई 2023 में गोवा में आयोजित ग्रीन फाइनेंस समिट में हस्ताक्षरित MoU के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है?

A) समिट के दौरान, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC लिमिटेड) ने कुल 5 लाख करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने के लिए क्लीन एनर्जी कंपनियों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

B) इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन (CV) निर्माता PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने मार्च 2028 तक अपने वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के लिए 480 करोड़ रुपये का वित्त प्रदान करने के लिए REC लिमिटेड के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

C) रिन्यू ने अपनी वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने और कंपनी को बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण जुटाने में सक्षम बनाने के लिए PFC और REC के साथ 64,000 करोड़ रुपये के MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

1) सभी A, B & C

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) केवल A

उत्तर- 1) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC लिमिटेड) ने गोवा में आयोजित "ग्रीन फाइनेंस समिट" के दौरान अपनी परियोजनाओं के लिए कुल 5 लाख करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने के लिए क्लीन एनर्जी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- PFC ने क्लीन एनर्जी क्षेत्र की 20 कंपनियों के साथ 2.37 लाख करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए। REC ने 2.75 लाख करोड़ रुपये में करार किया।
- समिट का आयोजन REC लिमिटेड द्वारा 19 से 22 जुलाई, 2023 के बीच गोवा में 14वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग (CEM14/MI-8) के मौके पर भारत सरकार के ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) प्रेसीडेंसी के साथ साझेदारी में किया गया है।
- इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन (CV) निर्माता PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने मार्च 2028 तक अगले पांच वर्षों में अपने वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के लिए 480 करोड़ रुपये का वित्त प्रदान करने के लिए REC लिमिटेड के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ACME ग्रुप ने ओमान में अपने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए REC के साथ 4,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
- रिन्यू ने अपनी वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने और कंपनी को बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण जुटाने में सक्षम बनाने के लिए PFC और REC के साथ 64,000 करोड़ रुपये के MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- SJVN लिमिटेड ने REC लिमिटेड के साथ बैटरी स्टोरेज, E-वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया, हाइड्रोजन सेल स्टोरेज, ग्रीन परियोजनाओं के लिए विनिर्माण इकाइयों और ऊर्जा के पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों पर बिजली उत्पादन स्टेशनों जैसी प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपनी परियोजनाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए MoU किया है।
- जुनिपर ग्रीन एनर्जी ने अपनी 1200 MW रिन्यूएबल एनर्जी (RE) परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के लिए PFC के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

95. जुलाई 2023 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने और सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने के लिए _____ (योजना/मिशन) के तहत _____ माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की।

- 1) 500; प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
- 2) 100; आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 3) 500; मिशन इंद्रधनुष
- 4) 100; प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
- 5) 400; आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

उत्तर- 2) 100; आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

स्पष्टीकरण:

28 जुलाई, 2023 को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने और सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की।

- परियोजना ABDM के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जबकि NHA वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- माइक्रोसाइट्स पूरे भारत में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में स्थापित की जाएंगी।
- माइक्रोसाइट्स ABDM-सक्षम छोटे और मध्यम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे क्लीनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल (10 बिस्तरों से कम वाले), प्रयोगशालाएं और फार्मसियों के समूह हैं, जो मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

96. जुलाई 2023 तक वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु "सही" है/हैं?

A) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दौरान AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) नामक लिमिटेड पर्पज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (LPCC) तंत्र पर व्यापार की शुरुआत की।

B) केंद्रीय मंत्री ने कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF), म्यूचुअल फंड (MF) के लिए 33,000 करोड़ रुपये की बैकस्टॉप सुविधा का भी उद्घाटन किया।

C) केंद्रीय मंत्री ने ARCL के माध्यम से पेश कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो लॉन्च किया, जो एक LPCC है जिसका उद्देश्य भारत में अंतर्निहित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को विकसित करना है

1) केवल A

2) केवल A & B

3) केवल B & C

4) केवल A & C

5) सभी A, B & C

उत्तर - 5) सभी A, B & C

स्पष्टीकरण:

28 जुलाई, 2023 को वित्त मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई, महाराष्ट्र में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) नामक लिमिटेड पर्पज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (LPCC) तंत्र पर व्यापार की शुरुआत की।

- उन्होंने कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) का भी उद्घाटन किया।
- दोनों पहलों का उद्देश्य कॉर्पोरेट डेट मार्केट के कामकाज को गहरा करना है।

ii. केंद्रीय मंत्री ने ARCL के माध्यम से पेश कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो लॉन्च किया, जो एक LPCC है जिसका उद्देश्य भारत में अंतर्निहित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को विकसित करना है

ii. CDMDF म्यूचुअल फंड (MF) के लिए 33,000 करोड़ रुपये की बैकस्टॉप सुविधा है, जिसे पहली बार 2021-22 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। इसे मार्च 2023 में SEBI द्वारा अनुमोदित किया गया था।

97. उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में (जुलाई'23 में) नई दिल्ली, दिल्ली में एक वर्चुअल म्यूजियम, मेरा गांव मेरी धरोहर (MGMD) का वर्चुअल पोर्टल लॉन्च किया है।

- 1)पर्यटन मंत्रालय
- 2)गृह मंत्रालय
- 3)संस्कृति मंत्रालय
- 4)ग्रामीण विकास मंत्रालय
- 5)शिक्षा मंत्रालय

उत्तर-3)संस्कृति मंत्रालय

स्पष्टीकरण:

27 जुलाई 2023 को, संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (MoS) अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली, दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में मेरा गांव मेरी धरोहर (MGMD) का वर्चुअल पोर्टल लॉन्च किया, जो एक वर्चुअल म्यूजियम है जो भारत के 6.5 लाख से अधिक गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करता है।

i.लॉन्च का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण जीवन की पहचान और दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गांवों के बारे में जानकारी को एकीकृत करना है।

ii.MGMD के तहत विकसित इंटरैक्टिव वेब पोर्टल कलाकारों और शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (NCWP) के रूप में काम करेगा और संस्कृति सेवा प्रदाताओं के लिए एकल विंडो ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा।

98. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में (जुलाई'23 में) किस राज्य में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय (PBKIVV) के "डिवाइन लाइट हाउस" की आधारशिला रखी है?

- 1)ओडिशा
- 2)पश्चिम बंगाल
- 3)आंध्र प्रदेश
- 4)महाराष्ट्र
- 5)तेलंगाना

उत्तर- 1)ओडिशा

स्पष्टीकरण:

27 जुलाई 2023 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 से 27 जुलाई 2023 तक ओडिशा की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दसाबटिया, तमांडो, भुवनेश्वर (ओडिशा) में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय (PBKIVV) के "डिवाइन लाइट हाउस" की आधारशिला रखी।

i.राष्ट्रपति ने राष्ट्रव्यापी सेमिनार और सम्मेलनों के आयोजन के लिए PBKIVV के 2023 के विषय "द ईयर ऑफ़ पॉजिटिव चेंज" भी लॉन्च किया।

INTERNATIONAL AFFAIRS

1. जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी रिपोर्टबर्डन ऑफ़ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन: 2019 अपडेट के अनुसार, _____ साल से कम उम्र के बच्चों में, असुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा (WASH) 395,000 मौतों के लिए जिम्मेदार था।

- 1)3
- 2)5
- 3)10
- 4)6
- 5)14

उत्तर- 2)5

स्पष्टीकरण:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट बर्डन ऑफ़ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन: 2019 अपडेट के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, असुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा (WASH) 395,000 मौतों और 37 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (DALY) के लिए जिम्मेदार था। यह इस आयु वर्ग में सभी मौतों का 7.6% और सभी DALY का 7.5% है।

i. इसमें डायरिया से 273,000 मौतें और तीव्र श्वसन संक्रमण से 112,000 मौतें भी शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के शीर्ष 2 संक्रामक कारण हैं।

ii. रिपोर्ट वर्ष 2019 के लिए 183 WHO सदस्य देशों के लिए असुरक्षित WASH के कारण रोग विशेषताओं के बोझ का अनुमान प्रदान करती है।

iii. रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की आधी आबादी के पास अभी भी पीने के पानी, स्वच्छता और स्वच्छता तक पर्याप्त पहुंच नहीं है, जिसके कारण 2019 में कम से कम 1.4 मिलियन लोगों की मौत और 74 मिलियन DALY हुईं।

2. जुलाई 2023 में विश्व बैंक (WB) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा सह-प्रकाशित 'ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट: फोस्ट्रिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकनोमिक डायवर्सिफिकेशन' नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने _____ में 2% से 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना कर 4.4% कर दिया है।

1)2010

2)2005

3)2009

4)2007

5)2008

उत्तर- 2)2005

स्पष्टीकरण:

विश्व बैंक (WB) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा सह-प्रकाशित 'ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट: फोस्ट्रिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकनोमिक डायवर्सिफिकेशन' नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2005 में 2% से 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना कर 4.4% कर दिया है।

i. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने 2005 से 2022 तक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के अपने हिस्से को 3% से 5.4% तक दोगुना कर दिया है।

ii. रिपोर्ट को WTO के महानिदेशक, डॉ नगोजी ओकोंजो-इवेला और विश्व बैंक के अध्यक्ष, अजय बंगा द्वारा 3 जुलाई 2023 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।

iii. चीन, हांगकांग, सिंगापुर और भारत सेवाओं के शीर्ष निर्यातक और आयातक हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार प्रदर्शन को संचालित कर रहे हैं।

iv. भारत एक पसंदीदा चिकित्सा यात्रा केंद्र के रूप में उभरा है, जिसने 2009 और 2019 के बीच लगभग 3.5 मिलियन विदेशी रोगियों को आकर्षित किया है।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में (जुलाई '23 में) रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के लिए एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया है?

1) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन

2) संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन

3) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

4) 1 और 2 दोनों

5) सभी 1, 2 और 3

उत्तर- 5) सभी 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण:

28 जून 2023 को, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH), "चतुर्भुज संगठन" ने एक वेबिनार के माध्यम से "रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के लिए एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा" लॉन्च किया। अनुसंधान एजेंडा का उद्देश्य AMR में बढ़े हुए अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देना है।

i. एजेंडा 'एक स्वास्थ्य' को एक एकीकृत, एकजुट दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य लोगों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करना है।

4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) - संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के जल आपूर्ति, सफाई एवं स्वच्छता के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (JMP) की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर महिलाएं और लड़कियां पेयजल, सफाई एवं स्वच्छता (WASH) संकट का बोझ उठाती हैं।

विश्व स्तर पर, लगभग _____ लोग परिसर में जल की आपूर्ति के बिना घरों में रहते हैं।

1) 1.5 बिलियन

2) 1.6 बिलियन

3) 1.8 बिलियन

4) 2.0 बिलियन

5) 1.2 बिलियन

उत्तर- **3) 1.8 बिलियन**

स्पष्टीकरण:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) - संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की जल आपूर्ति, सफाई एवं स्वच्छता के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (JMP) की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक "प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन 2000-2022: स्पेशल फोकस ऑन जेंडर" है, विश्व स्तर पर महिलाएं और लड़कियाँ जल, सफाई एवं स्वच्छता (WASH) संकट का बोझ उठाती हैं।

- पुरुषों की तुलना में महिलाएं और लड़कियाँ घरों के लिए जल लाने में दस गुना अधिक समय खर्च करती हैं।
- जिम्मेदारी उठाने की संभावना लड़कों की तुलना में लड़कियों की लगभग दोगुनी होती है।

नोट: यह घरों में WASH में लैंगिक असमानताओं का पहला गहन विश्लेषण है।

रिपोर्ट का सार:

i. विश्व स्तर पर, लगभग **1.8 बिलियन लोग** परिसर में जल की आपूर्ति के बिना घरों में रहते हैं।

ii. परिसर में जल की आपूर्ति के बिना 10 घरों में से 7 में जल संग्रह के लिए महिलाएं और लड़कियाँ (उम्र 15 या उससे अधिक) जिम्मेदार हैं।

5. उस देश का नाम बताइए जो हाल ही में (जुलाई 23 में) ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप (GCRG) के चैंपियन ग्रुप में शामिल हुआ है।

1) ब्राज़ील

2) रूस

3) फ्रांस

4) भारत

5) यूक्रेन

उत्तर- **4) भारत**

स्पष्टीकरण:

7 जुलाई 2023 को, विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की कि **भारत** के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव (SG) एंटोनियो गुटेरेस के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप (GCRG) के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया है।

- MEA के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा को GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है।

i. खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण ग्लोबल मुद्दों को निर्देशित करने और ग्लोबल रिस्पॉन्स के समन्वय के लिए मार्च 2022 में UN SG द्वारा GCRG की स्थापना की गई थी।

ii. 32 सदस्यीय ग्रुप खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्तपोषण की विशाल अंतर-जुड़ी चुनौतियों से आगे निकलने और मौजूदा संकटों के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित करता है।

iii.GCRG के अध्यक्ष UN SG एंटोनियो गुटेरेस होंगे।

6. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रांकोइस-जेवियर बैगनॉड सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स (FXB) के साथ किस संगठन ने प्रमुख निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट जारी की कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की ट्रैफिकिंग उनके ही देश में की जाती है?

- 1)यूनाइटेड नेशंस चिल्डर्न फण्ड
- 2)इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन
- 3)यूनाइटेड नेशंस हाई कमिशनर फॉर रेफुजीस
- 4)यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम
- 5)इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन

उत्तर-2)इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन

स्पष्टीकरण:

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रांकोइस-जेवियर बैगनॉड सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स (FXB) ने 'फ्रॉम एविडेंस टू एक्शन: ट्रेटी इयर्स ऑफ IOM चाइल्ड ट्रैफिकिंग डाटा टू इन्फॉर्म पालिसी एंड प्रोग्रामिंग' शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट के अनुसार, आधे चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की ट्रैफिकिंग उनके ही देश में की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिकिंग के मामलों में चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग ज्यादातर पड़ोसी, अमीर देशों में की जाती है।

i. यह रिपोर्ट, अपनी तरह की पहली, IOM के विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग डेटाबेस (VoTD) का उपयोग करते हुए, व्यापक, विश्व स्तर पर प्राप्त डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें 186 देशों में ट्रैफिकिंग कर लाए गए 156 राष्ट्रीयताओं के 69,000 से अधिक विक्टिम्स के प्राथमिक डेटा का विश्लेषण किया गया।

ii. VoTD ट्रैफिकिंग के व्यक्तिगत विक्टिम्स का सबसे बड़ा उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस है। डेटाबेस में 18.3% VoT बच्चे थे।

7. जुलाई 2023 में, यूनाइटेड नेशंस (UN) इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन (IMO) ने _____ के करीब अंतरराष्ट्रीय शिपिंग से ग्रीनहाउस गैसेस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए 2023 IMO रणनीति अपनाई।

- 1)2040
- 2)2030
- 3)2025
- 4)2050
- 5)2035

उत्तर- 4)2050

स्पष्टीकरण:

7 जुलाई 2023 को, यूनाइटेड नेशंस (UN) इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन (IMO) ने हानिकारक उत्सर्जन से निपटने के लिए उन्नत लक्ष्यों के साथ जहाजों से ग्रीनहाउस गैसेस (GHG) उत्सर्जन में कमी पर मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी (MEPC) में 2023 IMO रणनीति को अपनाया।

i. संशोधित IMO GHG रणनीति का लक्ष्य 2050 के करीब अंतरराष्ट्रीय शिपिंग से शुद्ध-शून्य GHG उत्सर्जन तक पहुंचना है।

ii. IMO ने शून्य ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों, ईंधन और ऊर्जा स्रोतों को अपनाने का एक लक्ष्य भी स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य न्यूनतम 5% गोद लेने की दर और वर्ष 2030 तक 10% की उच्च गोद लेने की दर के लिए प्रयास करना है।

8. जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा हस्ताक्षरित MoU के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु "सही" है/हैं?

A) IFSCA और CPI-इंडिया ने भारत में वैश्विक स्थायी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए आपसी सहायता और सहयोग के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

B) IFSCA ने FinTech और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग और आपसी समझ के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए IIM लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर (IIML EIC) के साथ एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

C) इसके तहत, IIML EIC के साथ पंजीकृत FinTech को IFSCA के नियामक और नवाचार सैंडबॉक्स तक पहुंचने और IFSCA (FinTech प्रोत्साहन) योजना, 2022 पर आवेदन करने की सुविधा दी जा सकती है।

- 1)केवल A
- 2)केवल A & B